● वर्ष-3
● अंक-55
रायपुर, गुरुवार
12 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› पहली बार 2018 विस चुनाव...

सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पर भड़के हिमंत सरमा, पाकिस्तान और तालिबान से कर दी तुलना

आतंकवाद और बंधकों की हत्या पर मौन कांग्रेस

नई दिल्ली। युद्ध के नए दौर के बीच फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में कांग्रेस के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बयान में पाकिस्तान और तालिबान के बयानों के साथ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा कि तीन पहलुओं में समानताएं हैं। कांग्रेस का प्रस्ताव हमास की निंदा न करें, इज़राइल पर आतंकवादी हमले की निंदा न करें और बंधकों महिलाओं और बच्चों पर चुप रहें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के हित की बलि चढ़ाना कांग्रेस के डीएनए में है।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि उसे फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्व-शासन और गरिमा और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए लंबे समय से समर्थन प्राप्त है। इसने इज़रायली बलों और हमास आतंकवादियों के बीच तत्काल संघर्ष विराम का भी आह्वान किया। सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्व-शासन और गरिमा और

सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी तत्काल युद्धविराम का आह्वान करती है और सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है, जिसमें वे अनिवार्य मुद्दे भी शामिल हैं, जिन्होंने वर्तमान संघर्ष को जन्म दिया है।

इसे असम के मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। प्रस्ताव को लेकर भाजपा द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद पार्टी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही रुख अपनाया था। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद, भाजपा केवल कांग्रेस के बारे में बात कर रही है और अपने इतिहास के साथ-साथ वाजपेयीजी के भाषण को भी भूल गई है।

राजनीतिक मुद्दा बना रही भाजपा - थरूर

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि इजरायल-हमास युद्ध के बीच %फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करने वाला उनकी पार्टी का बयान किसी भी तरह से इस मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण नहीं था। थरूर ने कहा, यह किसी भी तरह से मुद्दे का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। अपने रुख के बारे में विस्तार से बताते हुए थरूर ने कहा, मैं समझता हूं कि बीजेपी एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। यह एक उभरती हुई तस्वीर है और हमारी प्रतिक्रियाएँ भी विकसित होंगी। पहले से ही अपने आप में बहुत अधिक विस्तृत बयान मौजूद है। उन्होंने आगे कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित थी और सामाजिक-आर्थिक व जातिगत जनगणना के सवाल पर केंद्रित थी। यह मुद्दा हर चीज पर हावी था।कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आपको याद होगा।

दिल्ली से चुराकर हमास को भेजी गई थी क्रिप्टोकरेंसी

क्या भारत से पैसा कभी फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूहों को भेजा गया था? 2022 में दिल्ली पुलिस द्वारा क्रैक किए गए क्रिप्टोकरेंसी मामले को देखते हुए कहा जा रहा है कि दिल्ली से गाजा स्थित आतंकवादी समूह हमास तक पैसे का एक रास्ता हो सकता। यह मामला इजरायल-हमास युद्ध और इजरायली अधिकारियों के रहस्योद्घाटन के बीच फिर से सामने आया है कि हमास इसके माध्यम से धन की मांग कर रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 2022 में क्रिप्टोकरेंसी चोरी की दिल्ली पुलिस की जांच से पता चला कि दिल्ली के एक व्यक्ति के वॉलेट से चुराए गए क्रिप्टो को हमास आतंकवादियों के खातों में भेज दिया गया था। यह मामला उन खबरों के बीच फिर से सामने आया है कि हमास ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए धन जुटाने का अभियान शुरू किया है। पुलिस शिकायत के अनुसार, व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से 2022 में एक खाते से लगभग 30 लाख रुपये मूल्य के बिटकॉइन, एथेरियम और बिटकॉइन कैश ट्रांसफर कर लिए। अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया और जांच साइबर अपराध इकाई की विशेष शाखा को स्थानांतरित कर दी गई। क्रिप्टो को मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला के वॉलेट में भी जमा किया गया था, लेकिन खातों को इज़राइल द्वारा आतंक-वित्तपोषण कार्रवाई में जब्त कर लिया गया था।

पुरकायस्थ के आवास पर मारा छापा सीबीआई ने अपने हाथ में लिया मामला

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक द्वारा विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही, बुधवार को दो स्थानों पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि सीबीआई की एक टीम ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के आवास और कार्यालय की तलाशी ली। बता दें, पुरकायस्थ को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया था।

एक अधिकारी ने बताया कि पोर्टल पर आरोप है कि उसने विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) मामले का उल्लंघन करते हुए विदेशी चंदा प्राप्त किया है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आरोप लगाया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य नेविल रॉय सिंघम ने फर्जी तरीके से विदेशी फंड का निवेश किया था। हालांकि, पोर्टल ने इन आरोपों का खंडन किया है।

क्या है न्यूज क्लिक से जुड़ा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हुई थी। जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि साल 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला। इतना ही नहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ मिले थे। यह पैसा कुछ जर्नलिस्ट में शेयर हुआ था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था नोटिस जारी

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बीती 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज क्लिक के सीईओ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था। जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जिसमें जांच एजेंसी को कोई भी जबरदस्ती न करने के लिए कहा गया था।

इन धाराओं में हुआ था मामला दर्ज

इस मीडिया पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई होईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित कर कहा था कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह भी कहा कि जांच अधिकारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।

सचिन के 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा

रोहित शर्मा ने विश्व कप में लगाए सर्वाधिक शतक

नई दिल्ली। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार (11 अक्तूबर) को वनडे विश्व कप में इतिहास रच दिया। उन्होंने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली। रोहित वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने इस मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोहित के नाम सात शतक हो गए। तेंदुलकर ने छह शतक लगाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए। उन्होंने 84 गेंद की पारी में 16 चौके और पांच छक्के लगाए। रोहित शर्मा को पहली बार 2015 में विश्व कप खेलने का मौका मिला था। उन्होंने उस संस्करण में एक शतकीय पारी खेली थी। इसके चार साल बाद जब 2019 में इंग्लैंड के मैदान पर वह विश्व कप खेलने

उतरे तो उन्होंने पांच शतक ठोक दिए थे। अब अफगानिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर उन्होंने तेंदुलकर के 12 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सचिन ने 1992 से 2011 तक छह विश्व कप के दौरान 45 मैच में छह शतक लगाए थे। रोहित ने विश्व कप के अपने 19वें मैच में ही उन्हें पीछे छोड़ दिया। रोहित ने 63 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। वह वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस मामले में रोहित ने महान कप्तान कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपिल देव ने 1983 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंद पर ही शतक ठोक दिया था। कपिल देव के बाद वीरेंद्र सहवाग का नंबर है। उन्होंने 2007 में बरमुडा के खिलाफ 81 गेंद पर शतक जड़ा था।रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। इस मैच में उतरने से पहले हिटमैन को सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए तीन छक्के की जरूरत थी। क्रिस गेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 553 छक्के लगाए थे। उन्होंने ऐसा 483 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 551 पारियों में किया था। वहीं, रोहित ने सिर्फ 453 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 473वीं पारी में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। उनके 556 छक्के हो गए। रोहित ने बतौर ओपनर वनडे में 29वां शतक लगाया। वह बतौर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गए। उन्होंने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ा। जयसूर्या के नाम 28 शतक हैं। रोहित के 29 शतक हो गए। इस मामले में उनसे आगे अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। उनके बतौर ओपनर 45 शतक हैं।

इस हॉल में आयोजन कराने के लिए आयोजक को 25 लाख रुपये प्रतिदिन का किराया देना होगा। अगर ग्रांउट फ्लोर पर बैठक का आयोजन करना है तो इसके लिए मीटिंग रूम का किराया एक लाख 30 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

प्रमुख समाचार

कोर्ट ने आतंकवादी लखबीर की भूमि जब्त करने का आदेश दिया

नई दिल्ली। पंजाब में मोहाली की एक एनआईए अदालत ने घोषित आतंकवादी व पाकिस्तान में रह रहे 'खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट' के स्वयंभू सरगना लखबीर सिंह उर्फ रोडे की राज्य के मोगा जिले में स्थित ज़मीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। एक

अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अदालत ने गैर कानून गतिविधि रोकथाम कानून 1967 की धारा 33(5) के तहत कोठे गुरुपुरा गांव में स्थित सिंह की भूमि को जब्त करने का आदेश दिया है। इस धारा के तहत न्यायाधीश गंभीर अपराधों में शामिल भगोड़े अपराधियों की चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकते हैं। इसने यह आदेश राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा एक जनवरी 2021 को यूएपीए, भारतीय दंड संहिता और मादक पदार्थ संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज किए गए एक मामले में दिया है। लखबीर सिंह जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा है। 15 सितंबर 2021 को फज़लिका जिले के जलालाबाद शहर में हुए टिफिन बम विस्फोट मामले में संलिप्तता को लेकर पंजाब पुलिस ने शुरू में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के नाम सुझाए

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 13 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय

किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इसने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायिक अधिकारियों- शालिंदर कौर और रविंदर डुडेजा के नाम की सिफारिश की। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से 30 मई को न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा कि विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पीठ में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि कौर 30 सितंबर, 2023 को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुई हैं। इसने कहा, ''इसके बावजूद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकारी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है।

राजद्रोह कानून खत्म होने से भी विपक्ष को सता रही चिंता

नई दिल्ली। राजद्रोह कानून की विपक्ष हमेशा आलोचना करता रहा है। केंद्र में चाहे जिस दल की सरकार रही हो, विपक्ष ने हमेशा इस बात का आरोप लगाया है कि केंद्र सरकारें इसके जरिए अपने राजनीतिक-वैचारिक विरोधियों को डराने का प्रयास करता रहा है। यही कारण है कि विपक्षी दलों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय और सामाजिक संस्थाएं भी इसे समाप्त किए जाने की मांग करती रही हैं। लेकिन अब जब कि केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और उसके स्थान पर नए कानून लाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को इस बात की चिंता सताने लगी है कि राजद्रोह कानून समाप्त करने के नाम पर उससे भी ज्यादा कठोर कानून लाया जा सकता है और इसके जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक ट्वीट कर अपनी यही चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नए कानून लाने के लिए जो प्रस्ताव किए हैं, वे कहीं ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं।

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हुई शुरू, खास होगा आयोजन

नई दिल्ली। अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर तैयार होने वाला है। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी जोर-शोर से की जा रही है। वही दिवाली के मौके पर अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव के आयोजन को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। दीपोत्सव के संबंध में जिला प्रशासन और अवध विश्वविद्यालय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस वर्ष अयोध्या में सातवां दीपोत्सव का आयोजन होना है जो की बेहद दिव्या और भाव होने वाला है। राम की पैड़ी के घाटों पर इस वर्ष 24 लाख दीपों को जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वही इस वर्ष भी नया कीर्ति महान बनाए जाने की तैयारी है जिसमें 21 लाख से अधिक दीपक को एक साथ जलाया जाएगा। बता दें कि इतनी संख्या में दीपों को जलाने के लिए 25000 से अधिक वॉलिंटियर्स आगे आए। यह सभी वॉलिंटियर्स स्कूल-कॉलेज के छात्र है। इस दौरान लेजर और ड्रोन शो का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। यीशु की खासियत है कि यह शो प्रभु श्री राम के जीवन को प्रदर्शित करता है। ऐसे बेहद शानदार आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग और प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि जबसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है।

भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, ब्रह्मोस का परीक्षण

नई दिल्ली।भारतीय वायु सेना (द्धस्न) ने हाल ही में पूर्वी समुद्री तट द्वीपसमूह के पास ब्रह्मोस मिसाइल के सतह से सतह पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया। मिसाइल फायर सफल रहा और मिशन ने अपने सभी उद्देश्य हासिल कर लिए। परीक्षण-

फायरिंग पूर्वी द्वीपसमूह के पास आयोजित की गई थी। भारतीय वायुसेना ने कहा कि मिसाइल फायर सफल रहा और मिशन ने अपने सभी उद्देश्य हासिल कर लिए। रक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि भारतीय वायु सेना सहित भारतीय रक्षा बलों ने पिछले दो दिनों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के चार परीक्षण किए। विस्तारित दूरी की मिसाइलों ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया। परीक्षण-फायरिंग की तस्वीरें और वीडियो द्धस्न द्वारा अपने आधिकारिक %ङ्क% हैंडल पर साझा किए गए थे। इस बीच, ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने भारतीय सशस्त्र बलों की मारक क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत का ध्वजवाहक बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।

तनाव

अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहा कर्मचारियों का तनाव

कर्मचारियों का तनाव केवल उनकी कार्य क्षमता ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह पूरी कंपनी की बैलेंस शीट भी खराब कर रहा है। तनाव के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आती है। कर्मचारियों में तनाव के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हर साल अपनी जीडीपी का लगभग 1.6 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत को भी अपने कर्मचारियों में तनाव के कारण प्रतिवर्ष जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत का नुकसान सहना पड़ता है। मनोरोग विशेषज्ञों का कहना है कि जिस खतरनाक गति से कर्मचारियों में तनाव बढ़ रहा है, आने वाले समय में यह एक महामारी साबित हो सकता है और इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। कुल अमेरिकी कर्मचारियों का लगभग 22.8 प्रतिशत किसी न किसी मानसिक बीमारी से परेशान है और इस कारण कंपनियों को हर साल 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। जबकि भारत में अभी कुल आबादी के लगभग दस प्रतिशत लोग ही मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, इसके बाद भी भारत को हर साल लगभग 46 बिलियन डॉलर का नुकसान हर साल होता है। मनोरोग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कर्मचारियों में आपस की राजनीति, वरिष्ठों का हर कर्मचारी के प्रति एक जैसा व्यवहार, कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा दिए जा रहे टारगेट को कम करके अनावश्यक तनाव को कम किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कंपनी की कुल उत्पादकता बढ़ जाती है। आधुनिक प्रबंधन तकनीक में दुनिया की सबसे टॉप कंपनियों में भी कर्मचारियों की संतुष्टि को सबसे ऊपर रखा जाता है जिसका असर उनकी बैलेंस शीट में दिखाई पड़ता है।

केवल 23 प्रतिशत को ही इलाज

मेडिक्स ग्लोबल की फाउंडर और सीईओ सिगल एट्ज़्मों ने अमर उजाला से कहा कि अकेले भारत में लगभग 10 प्रतिशत लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और निमहांस के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल मानसिक पीड़ितों में केवल 23 प्रतिशत को ही इलाज मिल पाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि लगभग 12 करोड़ मानसिक पीड़ित लोगों को इस गंभीर समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। इसका परिणाम कभी आत्महत्या, कभी सामूहिक हत्या और

अक्सर तलाक और पारिवारिक समस्याओं के रूप में दिखाई पड़ता है।

इलाज न मिलने से मानसिक बीमारी बढ़ने और खतरनाक रूप लेने की संभावना बढ़ जाती है। स्वयं पीड़ित के अलावा परिवार के लोग भी अपने सदस्य को मानसिक बीमारी से पीड़ित बताने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें पागल समझने लगेंगे। लेकिन उचित इलाज कर इस समस्या को किसी भी अन्य बीमारी की तरह पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

अनुमान से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा तनाव

जेरी केयर हॉस्पिटल, चेन्नई के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीनिवास ने अमर उजाला से कहा कि हर साल किसी भी बीमारी के कारण व्यक्ति कुछ दिन अपना व्यावसायिक कार्य नहीं कर पाता है। इसकी गणना के आधार पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि किसी बीमारी के कारण व्यक्ति या कंपनी की उत्पादकता में कितना अंतर आ सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स कहा जाता है। प्रसिद्ध पत्रिका लैंसेट ने सबसे पहले इसकी गणना प्रकाशित की थी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनाव या मानसिक बीमारी के कारण उसकी कार्यक्षमता में भारी गिरावट आ सकती है। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि लगभग हर सातवें व्यक्ति के तनाव से पीड़ित होने के बाद भी इसमें से एक चौथाई को भी इलाज नहीं मिलता है। भारत में अभी इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि में एक प्रतिशत से काफी अधिक हो सकता है।

लाइफ स्टाइल नहीं, लाइफ को महत्व दें

सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ मनोचिकित्सक राजीव मेहता ने अमर उजाला से कहा कि हमें लाइफ स्टाइल की बजाय लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि ज्यादा पैसा कमा के भौतिक सुख-सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाने की बजाय आत्मीय संतोष को प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल इसी भावना को ध्यान में रखकर ही अनावश्यक तनाव और मनोरोगों से बचा जा सकता है।

कोंडागांव से पांचवी बार लड़ेंगी लता चुनाव, केशकाल से पहली बार मैदान में नीलकंठ टेकाम

■ लता उसेंडी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी तक अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशियों को उतारा है। वहीं चार प्रत्याशी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिन पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है।

कोंडागांव विधानसभा से पूर्व मंत्री रह चुकी लता उसेंडी पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। पार्टी ने लता उसेंडी को एक बार फिर विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। बीजेपी ने पूर्व मंत्री लता उसेंडी को लगातार पांचवीं बार चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले 2003 एवं 2008 के चुनाव में लता विजयी रही। जिसके बाद 2013 एवं 2018 के विधानसभा चुनाव में लता उसेंडी को कांग्रेस के मोहन मरकाम ने हराया था।

लता उसेंडी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1998 में की थी। 1998 में लता कांकेर में भाजपा की मंडल मंत्री रह चुकी हैं। 1999 में वह कोंडागांव नगर

पालिका से पार्षद निर्वाचित हुईं। साल 2000 में कांकेर जिला में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनीं। साल 2002 में कोंडागांव भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी। साल 2003 में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से लता उसेंडी पहली बार विधायक निर्वाचित हुईं। जिसके बाद साल 2004 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2005 से 2008 तक छत्तीसगढ़ शासन में बतौर मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार उनके पास रहा। 2008 में वह दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल व युवा कल्याण विभाग का प्रभार लता उसेंडी ने संभाला।

2013 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 से 2015 में लता छत्तीसगढ़ शासन में प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं। 2015 से 2018 तक छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। वहीं पार्टी ने 2018 विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन कांग्रेस के मोहन मरकाम ने उन्हें फिर से हरा दिया। 2019 से 2021 तक लता छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहीं और साथ ही प्रदेश प्रभारी भी रहीं। साल 2022 में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनीं। वर्तमान में अभी भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर वे पदस्थ हैं। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोंडागांव विधानसभा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है।

केशकाल से चुनावी मैदान में नीलकंठ टेकाम

केशकाल विधानसभा से इस बार बीजेपी ने नए उम्मीदवार पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम को मौका दिया है। नीलकंठ टेकाम ने सरकारी नौकरी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी। अब पहली बार केशकाल विधानसभा से नीलकंठ टेकाम चुनाव लड़ रहे हैं। केशकाल विधानसभा में लगातार दो बार से कांग्रेस के संतराम नेताम का कब्जा रहा है। नीलकंठ टेकाम साल 1990 से 1993 तक शासकीय महाविद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के रूप सेवा दे चुके हैं। साल 1994 से 2008 तक राज्य प्रशासनिक सेवा के जिये सीईओ जनपद पंचायत, एसडीएम, अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम के पद पर मध्य प्रदेश के धार, बड़वानी और छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर जिले में काम कर चुके हैं। साल 2008 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव राजस्व, संयुक्त सचिव जल संसाधन, संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा के पद पर भी उन्होंने काम किया है। साल 2017 से 2020 तक कोंडागांव में कलेक्टर के पद पर भी सेवाएं दी। फिर वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश किया है।

अकलतरा में रोचक होगा चुनावी संग्राम : सौरभ सिंह

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं।इसी कड़ी में बीजेपी ने अकलतरा से एक बार फिर सौरभ सिंह पर भरोसा जताया है। सौरभ सिंह ने टिकट मिलने पर खुशी जताते हुए प्रदेश में अपनी जीत के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। सौरभ सिंह की माने तो इस बार छत्तीसगढ़ की जनता केंद्र में मोदी शासन के कामों को ध्यान में रखकर प्रदेश में बीजेपी को चुनेगी।

सौरभ सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव निश्चित ही बहुत दिलचस्प होने वाला है। अकलतरा विधानसभा में हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय पार्टी से भी कमजोर रही। वहीं इस बार बीजेपी को कांग्रेस के अलावा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़,बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी से निपटना होगा। सौरभ सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाएं। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ सिंह ने कहा कांग्रेस को अब भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं, तभी तो इस चुनाव में कांग्रेस भूपेश के चेहरा पर चुनाव लड़ने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, इस बार प्रदेश की

जनता कांग्रेस को हराने के लिए तैयार है।

अकलतरा विधानसभा सीट में जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनाव में छाए रहते हैं। पिछले चुनाव में अकलतरा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की प्रत्याशी ऋचा जोगी दूसरे स्थान पर रही थी।वहीं कांग्रेस को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने जहां सौरभ सिंह को मैदान में उतारा है।वहीं आप ने आनंद मिरी और बसपा ने विनोद शर्मा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस और जेसीसीजे ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

बेमेतरा में अनशन पर बैठी पार्षद नीतू की तबीयत बिगड़ी

बेमेतरा। 3 अक्टूबर से राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि अंतरण मामले को लेकर अनशन पर बैठीं बेमेतरा पार्षद नीतू कोठारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत एंबुलेंस से बेमेतरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आमरण अनशन के कारण ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर-नीचे हो गया है। फिलहाल उनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है।

बेमेतरा की एसडीएम सुरुचि सिंह ने इस बारे में कहा कि, नगर पार्षद नीतू कोठारी राम मंदिर में आमरण अनशन पर बैठी हुई थी। जिनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद आगे फिर से आमरण अनशन करने की सलाह डॉक्टर ने नहीं दी है। कलेक्टर सर ने मामले को लेकर जांच टीम गठित की है। जल्द ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी।

दरअसल, ये पूरा मामला बेमेतरा के श्री राम मंदिर न्यास से जुड़ा हुआ है। यहां श्री राम मंदिर ट्रस्ट की लगभग साढ़े चार एकड़ की जमीन में बदलाव किया गया था। यहां श्री राम मंदिर न्यास के पदेन प्रबंधक तत्कालीन तहसीलदार आशुतोष गुप्ता और सुमित कौर के बीच सहमति बनाकर कोरोना काल के समय इसमें बदलाव किया गया था। तहसीलदार और एसडीएम की ओर से किए गए भूमि बदलाव को तुरंत कलेक्टर शिव अंनत तायल ने अपने नोट शीट में, गलत ठहराया है। अब मामले को लेकर दो साल बाद खुलासा हुआ। गलत तरीके से मंदिर की जमीन बदलने के मामले में भाजपा समर्थित पार्षद नीतू कोठारी आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। जिन्हें भाजपा विश्व हिंदू परिषद हिंदूवादी संगठन के लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से मामले को लेकर जांच टीम गठित की गई है। हालांकि सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक मामले की जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है।

कांकेर में चुनाव को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी

कांकेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी।जिसमें कांकेर जिले की तीन विधानसभा भी शामिल हैं। लिहाजा जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है।इसी कड़ी में पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।लिहाजा संवेदनशील बूथों के साथ विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। जिसकी जानकारी ईटीवी भारत से एसपी दिव्यांग पटेल ने साझा की।

कांकेर एसपी ने बताया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कांकेर पुलिस प्रशासन ने चुनाव के संबंध में पूरी तैयारी की है। फ्री, फेयर इलेक्शन हो इसके लिए लगातार फ्लैग मार्च करके लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया जा रहा है। कांकेर पुलिस जिले से लगे अलग-अलग चेकपोस्ट में वाहनों की चेकिंग कर रही है। जिले में 15 चेकपोस्ट लगाए गए हैं।चुनाव को लेकर कांकेर पुलिस का विशेष टीम का भी गठित किया गया है।

एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह चुनाव शांति पूर्वक हो सके। कांकेर क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आता है। हमारे द्वारा एरिया डोमिनेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

कांकेर पुलिस से जानकारी के अनुसार पुलिस और आबकारी विभाग ने तीन माह में आबकारी अधिनियम अंतर्गत 344 प्रकरण बनाकर अपराध दर्ज किया है। वहीं पुलिस और परिवहन विभाग ने अवैध परिवहन के 2150 मामले पकड़े हैं। जिसमें 5 लाख 55 हजार रुपये समन राशि वसूली की गई है। कानून और शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय के माध्यम से सजा देने की कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत तीन माह में जिले में 1431 व्यक्तियों के विरुद्ध 901 प्रकरण दर्ज किए गए हैं ।जिसमें 448 व्यक्तियों के खिलाई कार्यवाई की गई है। जिले में कुल 05 लाख 61 हजार 36 मतदाता हैं, जिनमें 02 लाख 74 हजार 222 पुरूष मतदाता, 02 लाख 86 हजार 802 महिला मतदाता एवं 12 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता हैं। कांकेर जिले में कुल 727 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिम नक्सल प्रभावित संवेदनशील 285 मतदान केंद्र है वही व्लनेरेबल मतदान केंद्र 35 क्रिटिकल मतदान केंद्र 30 और सामान्य मतदान केंद्र 377 है।

महिला शिक्षकों को निकटतम मतदान केंद्र में चुनावी ड्यूटी लगाने की मांग

कबीरधाम। कबीरधाम में मंगलवार को छग टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चन्द्रवंशी के नेतृत्व में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मतदान दल ड्यूटी में विसंगतियों पर चर्चा की। कलेक्टर की ओर से एडिशनल कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन ने ज्ञापन स्वीकार किया।

चर्चा के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि मतदान दल में स्कूल शिक्षा विभाग के कई व्याख्यातागण व पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों को मतदान अधिकारी क्रमांक तीन का दायित्व दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि व्याख्याता व प्रधान पाठक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद है। ऐसे में व्याख्याता व प्रधान पाठकों को पदानुरूप दायित्व दिया जाए। उदाहरणस्वरूप स्वामी करपात्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं डाइट महराजपुर के व्याख्याताओं को मतदान अधिकारी क्रमांक तीन बनाया गया है, जिनका प्रशिक्षण 11 व 12 अक्टूबर को होना है। मतदान दल में दिव्यांग व 60 साल से अधिक उम्र के शिक्षकों को भी

शामिल कर दिया गया है जबकि इन्हें मुक्त रखने के लिए एसोसिएशन ने पहले ही पत्र लिखा था। कई कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी एक से अधिक चुनावी दायित्व के लिए लगाया गई है। जिसके कारण वे परेशान हैं, ऐसे में एक ही दायित्व दिया जाए। एसोसिएशन ने मांग रखी है कि यदि महिला शिक्षकों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है तो उन्हें कार्यस्थल के निकटतम मतदान केंद्र में दायित्व दिया जाए। इस विषय पर निर्वाचन संबंधी कार्य से संबंधित डिप्टी कलेक्टर ऋतुराज सिंह बिसेन से भी चर्चा की। एडिशनल व डिप्टी कलेक्टर ने इस पर शीघ्र ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस दौरान प्रमुख रूप से केशलाल साहू, राजेश तिवारी, राजकिरण चन्द्रवंशी, दिनमधुर वर्मा, संतोष साहू, पन्ना लोधी, रामकुमार आदि उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ओजस्वी का कटा टिकट, बेटी ने कहा पापा के बलिदान का अपमान

दंतेवाड़ा। भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी दावेदारी कर रही थी, लेकिन उनका टिकट काटकर चैतराम को दे दिया गया है। इससे नाराज पूर्व विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए जारी वीडियो में कहा कि मेरे पिता भाजपा के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। पिता की मौत के बाद मां ओजस्वी पार्टी में निरंतर सक्रिय रहीं, बावजूद इसके भाजपा ने टिकट नही देकर पिता के बलिदानी का अपमान किया है। उल्लेखनिय है कि वर्ष 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट से स्वर्गीय भीमा मंडावी की जीत हुई थी। भीमा मंडावी कांग्रेस की देवती कर्मा को हराकर विजयी हुए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई थी। भीमा मंडावी के बाद पत्नी ओजस्वी मंडावी को पार्टी ने दंतेवाड़ा में उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया था, जिसमें ओजस्वी मंडावी कांग्रेस की देवती कर्मा से हार गई थी।

चुनाव प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने पर छह को नोटिस

मुंगेली। मुंगेली जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल दाउपारा में मतदान दलों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने आज निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली और अधिकारी-कर्मचारियों से निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी सवाल पूछे। संतोषजनक जवाब नहीं देने व प्रशिक्षण कार्य को गंभीरता से नहीं लेने पर छह अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण को गंभीरतापूर्वक लेने के तथा चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण तिवारी ने बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में 16 कक्षों में 560 अधिकारी-कर्मचारी तथा शासकीय हाईस्कूल करही में आठ कक्षों में 280 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण 12 अक्टूबर तक चलेगा।

आचार संहिता लगते ही एक्शन में पुलिस, किया पैदल मार्च

कोरबा। कोरबा में आदर्श आचार संहिता के लगते ही कोरबा की पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है और हर तरह के नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीती रात कोरबा पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को यह बताया कि आचार संहिता के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है अगर नियमों की अनदेखी की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता का प्रतिबंध लगने के साथ ही कोरबा की पुलिस सड़क पर उतर आई है और नियमों का पालन करने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। सभी तरह के अवैध कार्यों पर लगाम लगाने को लेकर कोरबा की पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को बताया कि अपराधों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईटीआई चौक से पुलिस का फ्लैग मार्च निकला और पूरे शहर का भ्रमण किया। फ्लैग मार्च कोसाबाड़ी चौक पर समाप्त हुआ।

प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य

बेमेतरा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 की तारीख के ऐलान के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, जनप्रतिनिधियों के लिए पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, पर्चे प्रकाशित करने में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने आज यहां कलेक्ट्रेट के दृष्टि सभा कक्ष में जिले के प्रिंटरों एवं मुद्रकों की बैठक ली। मास्टर ट्रेनर ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पम्पलेट, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा।

बागबाहरा में दो एक्स. ट्रेनों के प्रायोगिक ठहराव की सुविधा

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्वी तट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत बागबाहरा रेलवे स्टेशन में दो गाडियो का ठहराव दिया जा रहा है। 18573/18574 विशाखापटनम-भगत की कोठी-विशाखापटनम एक्सप्रेस का बागबाहरा एवं 22847/22848 विशाखापटनम-कूर्ला-विशाखापटनम एक्सप्रेस का बागबाहरा रेलवे स्टेशन में प्रायोगिक ठहराव की सुविधा दी जा रही है। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर छ: माह के लिए दिया जा रहा है। 12 अक्टूबर से विशाखापटनम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18573 विशाखापटनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस का बागबाहरा रेलवे स्टेशन में 12.48 बजे पहुंचकर 12.050 बजे रवाना होगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में 14 अक्टूबर से नौतनवा से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18574 भगत की कोठी-विशाखापटनम एक्सप्रेस का सलेमपुर रेलवे स्टेशन में 01.24 बजे पहुंचकर 01.26 बजे रवाना होगी।

भूस्खलन से बाधित केके लाइन 17 दिन बाद हुई बहाल

■ 13 अक्टूबर से शुरु होगी यात्री ट्रेन

जगदलपुर। भूस्खलन से बाधित केके लाइन बीती रात 9 बजे बहाल हो गई है, पहली मालगाड़ी रात 9 बजे गुजरी, लेकिन मालगाड़ी की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। आज से इस मार्ग पर मालगाडियां लौह अयस्क लेकर दौडने लगी हैं, किंतु यात्रियों को अभी यात्रा करने के लिए दो दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि पैसेंजर सहित सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को 12 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए इस लाइन की सभी यात्री ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने पहले

ही 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। परिस्थितियां सामान्य रहीं तो 13 अक्टूबर से पैसेंजर सहित सभी ट्रेने अपने निर्धारित समय पर दौडने लगेंगीं।

उल्लेखनिय है कि 24 सितंबर को मानबार-जड़ती स्टेशन के बीच बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया था, जिससे पहाड़ के मलबे और बड़े-बड़े पत्थर ट्रैक के ऊपर गिर गए थे। वहीं इस दौरान लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में परेशानी हो रही थी। विगत 17 दिनों में 25 जेसीबी और 450 मजदूर एवं रेलवे के कर्मचारी मिलकर रेल लाइन को बहाल करने में सफल रहे। बीते 10 वर्षों में पहली बार इतना बड़ा भूस्खलन हुआ जिससे केके रेल मार्ग 17 दिनों तक बंद रहा।

इस रूट पर सबसे अधिक रेलवे को कमाई लौह अयस्क के परिवहन से होता है। हर दिन इस रूट से किरंदूल से विशाखापटनम तक 15 मालगाडियों का संचालन होता है, आने जाने में इनके 30 फेरे लगते हैं। इस तरह प्रति मालगाड़ी से रेलवे को 60 से 70 लाख रुपए की कमाई होती है। इस हिसाब से प्रतिदिन रेलवे को 7 से 8 करोड़ रुपए की आमदनरी रेलवे को होती है। इतना ही नहीं पूरे देश में सबसे अधिक कमाई देने वाला रेलवे का रूट भी यही है। ऐसे में पिछले 17 दिन इस रूट में यात्री ट्रेनों के साथ मालगाडियों का संचालन भी बंद था। इस तरह रेलवे को करीब 112 करोड़ का नुकसान हुआ। बैलाडीला से विशाखापट्टनम जाने वाले आयरन ओर से रेलवे प्रशासन को एक दिन में 7 करोड़ मिलत किराया मिलता है। अब तक 119 करोड़ रुपये का नुकसान रेलवे प्रशासन को होने का अनुमान है।

सुकमा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम सुरक्षा बलों ने आईईडी किया डिफ्यूज

सुकमा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में नक्सली मोर्चे पर तैनात सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। नुक्सलियों ने सुरक्षाबल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी बम लगाए था। मुखबिर के सूचना पर जवान सर्च पर निकले और आईईडी बम को बरामद किया। जिसके बाद मौके पर ही आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है।

सुकमा जिले में नक्सल ऑपरेशन के उप पुलिस अधीक्षक रजत नाग ने बताया, सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के अतुलपारा के जंगल में नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी प्लांट करने की सूचना मुखबिर से मिली थी। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ 74वीं बटालियन और जिला बल की संयुक्त टीम को कार्रवाई के लिए अतुलपारा के जंगल में रवाना किया गया था। जहां जवानों ने जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया और आईईडी बरामद किया। रजत नाग एएसपी सुकमा ने कहा सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबल के जवानों ने जंगल से 1 किलो वजनी आईईडी बम बरामद किया है। सुरक्षाबलों ने बरामद आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया है।

मंगलवार को ही सुरक्षाबलों ने सुकमा के किंडरेलपाड़ और नागाराम के जंगलों में नक्सलियों के कैम्प में धावा बोला था। इस दौरान नक्सलियों के डेरे से बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई थी, जिसे मौके पर ही नष्ट किया था। नक्सलियों के कैम्प को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां करीब 100 से अधिक नक्सलियों के रहने का डेरा था। क्योंकि जैसे ही जवान नक्सलियों के डेरे में पहुंचे, वहां चूल्हे पर चावल पक रहा था। दरअसल, बस्तर संभाग के कई जिलों में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली हमेशा से आईईडी बम का इस्तेमाल करते आये हैं। जवानों को इससे काफी नुकसान भी हुआ है। आईईडी बम के साथ ही प्रेशर बम भी नक्सली लगाते हैं। जिसकी चपेट में जवानों के साथ ही इससे पहले मवेशी भी आये हैं। जिसे देखते हुए सुकमा पुलिस आईईडी बम को निष्क्रिय कर इसे एक बड़ी सफलता मान रही है।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुज शर्मा को बाहरी प्रत्याशी बताकर किया विरोध

रायपुर। बाहरी भगाओ, धरसींवा बचाओ की

बात कहते हुए धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता आज रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने ने धरसींवा विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रत्याशी बदलने की मांग की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सूरज टंडन और श्यामलाल वर्मा ने कहा कि कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए छालीवुड अभिनेता अनुज शर्मा को धरसींवा विधानसभा से चुनाव लड़ाने से स्थानीय भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी मांग की है कि बाहरी भगाओ, धरसींवा बचाओ के तहत प्रत्याशी बदलने की मांग पार्टी के बड़े नेताओं से कर रहे हैं।

अमित जोगी ने कांग्रेस और भाजपा को पति-पत्नी बताया

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के

प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस और भाजपा को पति-पत्नी बताया है। उन्होंने कहा कि, बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता दिन में तकरार और रात में प्यार वाला है। जोगी ने कहा कि, कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। भाजपा ने भी विपक्ष की भूमिका को सही ढंग से नहीं निभाया। अमित जोगी ने कहा कांग्रेस-बीजेपी में बगावत होने वाली है। हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। हमारी पार्टी में सभी का सम्मान किया जाएगा। हालांकि उनकी खुद की पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी,कौन होगा प्रत्याशी, क्या किसी से सीट साझा करेंगे अभी तक अता पता नहीं हैं। पिछली बार तो अजीत जोगी जीवित थे तब पांच सीट मिल गई थी,मां रेणु जोगी के अलावा सारे विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। तमाम बड़े नेता भी साथ नहीं हैं। ऐसे में पार्टी किस प्रकार उपस्थिति दर्ज करायेगी? बसपा ने पहले ही किनारा कर लिया है जो पिछली बार साथ थे।

हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य एवं अवसर परीक्षा वर्ष 2024 के परीक्षा फार्म भरने की तिथियां घोषित कर दी है। सामान्य शुल्क के साथ परीक्षार्थी 31 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही. के. गोयल ने बताया कि परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 01 नवम्बर से 15 नवम्बर तक और विशेष विलंब शुल्क के साथ 16 नवम्बर से 31 नवम्बर तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वाध्यायी मुख्य एवं अवसर परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी शासकीय एवं अशासकीय अग्रेषण संस्थाओं के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा फार्म भर सकते हैं।

राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में चार टीमें रही विजेता

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय द्वारा साई सेंटर आउटडोर स्टेडियम में उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बस्तर, बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग की टीम विजयी रही। इस प्रतियोगिता में सरगुजा, बस्तर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर एवं बिलासपुर टीमें भाग ले रही है। राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शासी निकाय गुरुकुल महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय तिवारी ने बिगुल बजाकर किया। वॉलीबॉल का पहला मुकाबला सरगुजा और बस्तर के बीच हुआ खेला गया जिसमें बस्तर की टीम विजेता रहे। दूसरा प्रतियोगिता बिलासपुर और जांजगीर के बीच हुआ जिसमें बिलासपुर की टीम विजेता रही। तीसरा प्रतियोगिता रायपुर और रायगढ़ के बीच हुआ जिसमें सेक्टर रायपुर की टीम विजेता रही और चौथा मुकाबला कोरबा और दुर्ग के बीच हुआ जिसमें दुर्ग की टीम विजयी रही।

राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा रायपुर

रायपुर। 3 से 13 जनवरी 2024 तक होने वाले राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारतीय तीरंदाजी संघ ने इस बार रायपुर को सौंपी है, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सब जूनियर टीम का चयन अगले माह किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और योग्य प्रशिक्षक की राज्य में कमी है अगर यह पूरी हो जाए तो छत्तीसगढ़ से भी अच्छे तीरंदाजी खिलाड़ी निकलने और भारत को आगामी दिनों होने वाले प्रतियोगिताओं को और अधिक पदक मिलने की उम्मीद है। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कैलाश मुरारका व अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ तींरदाजी संघ के पदाधिकारियों ने एशियन गेम्स में भारतीय तीरंदाजी टीम के प्रतिनिधि रहे कैलाश मुरारका का सम्मान भी किया। इस अवसर पर कैलाश ने रायपुर की मेजबानी में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाडियों को नकद इनाम देने की भी घोषणा की।

कांग्रेस की अहम बैठक में कैंडी क्रश खेलते हुए दिखे सीएम बघेल, भाजपा ने कसा तंज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उसके नेता अमित मालवीय की एक्स पोस्ट पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने सीएम को चुनाव-संबंधी पार्टी की बैठक के दौरान कैंडी क्रश खेलते हुए दिखाया था। अपने पलटवार में भूपेश बघेल ने कहा कि पहले भाजपा को ऐतराज़ था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, भौंरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि कल एक बैठक से पहले फ़ोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब भाजपा को उस पर ऐतराज़ है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज़ है। पर यह तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा।

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा। कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया हूँ, वो भी जारी रहेगा। बाकि छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। सीएम की कैंडी क्रश खेलते हुए तस्वीर पर बीजेपी नेता मालवीय ने बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जानते हैं कि उनकी सरकार वापस नहीं आएगी। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं, उन्हें पता है कि कितना भी संघर्ष कर लें, सरकार नहीं आएगी। शायद इसीलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चयन से जुड़ी बैठक पर ध्यान देने की बजाय कैंडी क्रश खेलना उचित समझा।

आपको बता दें कि आदिवासी मतदाताओं के प्रभुत्व

वाले छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव दो चरणों में होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को घोषणा की। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है। राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, हालांकि आप, हमार राज, अनुभवी आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम द्वारा नव स्थापित संगठन और सर्व आदि दल (एसएडी) जैसे कुछ नए शामिल हुए हैं, जिसका उद्देश्य गठबंधन बनाना है। अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का प्रभाव, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम को प्रभावित कर सकता है।

गंगाजल पर भी जीएसटी, क्या श्रद्धालु पूजा-पाठ न करें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने पर केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गंगाजल से जीएसटी हटाने की मांग की है। बघेल ने पोस्ट में कांग्रेस के पांच वर्ष और भाजपा के 15 वर्ष के शासनकाल का अंतर भी बताया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पोस्ट में लिखा है, अब गंगाजल पर भी जीएसटी, क्या श्रद्धालु पूजा-पाठ न करें? क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा तो ऐसी ही लग रही है। मोदी सरकार ने चार दिन पहले गंगाजल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय किया है। इससे नकली रामभक्त, सनातन संस्कृति के महिमा मंडन का ढोंग करने वाले और गोमाता की रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है।

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने आज दिल्ली जाएंगे सीएम बघेल

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस ने अब उन सीटों पर जोर दिया है, जहां पहले चरण में मतदान होना है। यहां भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए है और इसी सिलसिले में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सुबह दिल्ली रवाना हो रहे है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 20 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे।

इंटरनेट सेवा बंद कर चुनाव आयोग कराए चुनावः श्रीवास्तव

रायपुर। ईवीएम हैकिंग प्रक्रिया से बचने के लिए मतदान प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग इंटरनेट सेवा बंद

कराकर चुनाव कराया जाए जिससे कि ईवीएम हैकिंग की संभावनाओं से बचा जा सकें। उक्त बातें रोटी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने पत्रकारवार्त के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव व लोक सभा चुनाव में ईवीएम हैकिंग प्रक्रिया से बचने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने की सलाह दी थी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों का बताया कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके वोट को हैक किया जा सकता है इसलिए इंटरनेट सेवा बंद कराकर आगामी विधानसभा चुनाव कराया जाए जिससे चुनाव आचार संहिता का पालन भी ठीक से किया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों में चुनाव कि घोषणा की परंतु इस मुख्य विषय पर चुप्पी साधी रही। चुनाव आयोग ईवीएम हैकिंग की प्रक्रिया में खुद शामिल हैं तथा एक विशेष राजनैतिक पार्टी के पक्ष में खड़ा है, अगर इंटरनेट सेवा बंद कराकर चुनाव नहीं हुआ तो चुनाव बाद एक रेडीमेड रिज़ल्ट देशवासियों को मिलेगा।

हारे हुए लोगों पर दांव लगा रही भाजपा उनके पास कोई नया चेहरा नहीं : भूपेश

रायपुर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दो सांसदों और एक केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को टिकट दिए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। वह सरगुजा से सांसद हैं, लेकिन कोरबा से टिकट दिया गया। इसी तरह विष्णुदेव साय पत्थलगांव रहते हैं, तो उन्हें कुनकुरी से टिकट दिया गया। गोमती साय कुनकुरी रहती हैं तो उन्हें पत्थलगांव से टिकट दिया गया है। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। बीजेपी हारे हुए लोगों पर दांव लगा रही है।

सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने जिसको बहुत पहले ही नकार दिया था, उसे दोबारा टिकट दिया गया है। चाहे वो अमर अग्रवाल हो या राजेश मूणत या प्रेमप्रकाश पांडे सभी पर भाजपा ने फिर विश्वास जताया है। इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। हारे हुए लोगों को उतारा है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह को टिकट दिए जाने पर कहा कि अभी भी उनकी ही चल रही है। भले ही वो अरुण साव को बगल में बैठा लें पर चल उन्हीं की रही है। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनी जाती है। उन पर केवल थोपे जाते हैं। भाजपा की दूसरी संभावित सूची के वायरल होने पर कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर सूची लीक की थी। यदि ऐसा नहीं होता तो कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ चुकी होती। जो सूची लीक हुई थी, जारी लिस्ट में भी अधितर वहीं नाम हैं। ये सब बीजेपी की रणनीति के तहत हुआ है। यह जानबूझकर लीक किया गया है। सोशल मीडिया में पोस्ट को लेकर कहा कि बीजेपी अब निम्न स्तर पर उतर आई है। उनके ऑफिशियल पेज पर पोस्ट गलत ढंग से किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी अब अपने असली चेहरे पर आ गई है। अब उनका नकाब उतर चुका है। दो फेस में चुनाव कराए जाने पर कहा कि पहले भी दो चरण में चुनाव कराए गए थे।

कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी : कुमारी शैलजा

■ जो कहा वो किया यही कांग्रेस और भाजपा में अंतर

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले पांच सालों में सिर्फ जनता के लिए काम किया है।

प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के मुताबिक चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में चुनाव की तारीखें दे दी हैं।छत्तीसगढ़ में दो दिन मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को दक्षिणी हिस्से में होगा ।इसके बाद 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में वोटिंग होगी।जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कुमारी शैलजा ने कहा ये कहना गलत नहीं होगा कि हम पिछले पांच साल से तैयार हैं। हम भरोसा बरकारर, फिर से कांग्रेस सरकार के नारे के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं।हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया। बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है।

आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक

छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बस्तर की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों में वोटिंग के लिए महज 27 दिन बचे हैं।ऐसे में इन्हीं 27 दिनों में कांग्रेस को प्रत्याशियों की ना सिर्फ घोषणा करनी होगी।बल्कि यदि कहीं से बगावती सुर उठे तो उसे शांत भी करना होगा।साथ ही साथ चुनावी घोषणापत्र भी पार्टी को जारी करके जनता के सामने अपना रोडमैप पेश करना होगा।

शैलजा ने दिए कांग्रेस विधायकों के टिकट काटे जाने के संकेत!

छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में देर रात सम्पन्न हुई। जिसमें विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत शामिल हुए।

बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं।स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी।12 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस की सूची फाइनल होने को लेकर शैलजा ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ही उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करता है। वह किस पर क्या सहमति बनाएंगे वह उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुमारी शैलजा ने कहा सीईसी फाइनल लिस्ट जारी करेगा। उनकी जब फाइनल मुहर लगेगी तब कैंडिडेट की लिस्ट क्लियर होगी।

विधायकों के टिकट काटे जाने की अटकलों पर कुमारी शैलजा ने कहा-कुछ फेर बदल होता है। वह स्वाभाविक है।हमेशा हर चुनाव में कुछ ना कुछ फेरबदल होता है।किन कारणों से होता है वह अलग-अलग कारण होते हैं। कांग्रेस की सूची को लेकर बीजेपी बेसब्री से इंतजार कर रही है के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा- बीजेपी बेसब्र नहीं बल्कि चिंता में है। उन्हें चुनाव को लेकर बहुत चिंता है।

नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कसडोल में कांग्रेस बैठक के वायरल वीडियो पर किया कटाक्ष

■ कहा - कसडोल तो एक झाँकी है, पूरी पिक्चर बाकी है

रायपुर। कांग्रेस में टिकट की घोषणा से पहले ही जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, वह उस भरोसे के खत्म हो जाने का प्रमाण है, जिसके होने का दावा करके कांग्रेस और प्रदेश सरकार के लोग इठलाते फिर रहे हैं। कसडोल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बैठक के वायरल वीडियो का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा से शेष पाँच प्रत्याशियों की घोषणा पर सवाल करने वाले कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में भरोसे को लेकर किसी तरह की टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबाँ में झाँक लेना चाहिए।

चंदेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी तयशुदा पराजय से विचलित कांग्रेस और प्रदेश सरकार के लोग भाजपा की एकजुटता में भी मीन-मेख निकालकर अपनी हताशा को ढँकने की लाख कोशिश करें, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। कांग्रेस में सरकार को विधायकों

पर, मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री पर, विधायकों को सरकार पर, मंत्रियों को पार्टी के पदाधिकारियों पर, पार्टी के विधायकों और नेताओं को कार्यकर्ताओं पर और प्रदेश इकाई पर केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं रह गया है। हालत यह है कि कांग्रेस भरोसे की जर्जर काया मरणासन्न पड़ी है और कांग्रेस के लोगों को शीशे के घर में रहकर दूसरों के घरों पर पत्थर उछालने से ही फुर्सत नहीं है! श्री चंदेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव मुहाने पर आ गया है और कांग्रेस में आपसी खींचतान, मनमुटाव, अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी जब कांग्रेस ने एक भी टिकट घोषित नहीं की है तब यह हाल है तो अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है! यूँ तो कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी थुक्का फजीहत के दौर से गुजर रही है, पर कसडोल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बैठक का वायरल वीडियो बता रहा है कि भूपेश सरकार का भरोसे का सम्मेलन संगठन के स्तर पर ही कितना खोखला है!

उन्होंने कहा कि कसडोल में कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ कार्यकर्ताओं का आक्रोश सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस प्रभारी, विधायक शकुंतला साहू एवं क्षेत्र के कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। बैठक में कार्यकर्ता विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ़ अपनी तीखी नाराजगी जता रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन भी किया जा रहा है। इसी बैठक में विधायक शकुंतला साहू ने भी उन लोगों को बकवास नहीं करने की बात कहते हुए डाँट रही हैं। यह एक वीडियो यह बता रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। श्री चंदेल ने सीधा सवाल किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम नेता वैसे तो लोकतंत्र और संस्कारों की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी, मनमुटाव से इंकार करते रहते हैं, क्या यह सिर्फ खोखली बातें हैं? कांग्रेस में मचे इसी घमासान की वजह से कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के लिए तारीख-पर-तारीख ही मिल रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर क्षेत्र के 24 भाजपा नेताओं को दिया एक्स श्रेणी की सुरक्षा

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर क्षेत्र के 24 भाजपा नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी अशोक जुनेजा को निर्देशित किया है कि वह थ्रेट इनपुट को लेकर लाजिस्टिक मदद करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से अनुरोध है कि इस मंत्रालय को सूचित करते हुए उपरोक्त 24 राजनीतिक नेताओं को 31 दिसंबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ में एक्स श्रेणी सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए।

बस्तर संभाग के इन 24 नेताओं को यह सुरक्षा एक दो दिन के अंदर सशस्त्र जवान तैनात कर दिए जाएंगे। यह सुरक्षा 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। जिन भाजपा नेताओं को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई है उसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और कांकेर क्षेत्र में कार्य कर रहे नेता शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार

बीजापुर- श्रीनिवास मुदलियार जिला उपाध्यक्ष, कमलेश मंडावी जिला उपाध्यक्ष, लव कुमार रायडू जिला उपाध्यक्ष, फूलचंद गागड़ा प्रदेश युवा मोर्चा सदस्य, घासी राम नाग जिला

अध्यक्ष किसान मोर्चा, जगर लक्ष्मैया जिला सचिव, संजय लुक्कर जिला कोषाध्यक्ष, किरण देव पूर्व प्रदेश महासचिव, अधिवक्ता सुधीर पांडे प्रदेश सदस्य। **दंतेवाड़ा** - मनीष सुराणा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, रामू नेताम जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती कमला नाग पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जश्नवीर नेगी मंडल अध्यक्ष बारसूर, संतोष गुप्ता जिला महासचिव, कामो कुंजाम मंडल महासचिव बचेली, सत्यजीत सिंह चौहान जनपद उपाध्यक्ष, कुलदीप ठाकुर जनपद सदस्य, सोमडू कोर्राम मंडल अध्यक्ष कुआकोंडा, धीरेंद्र प्रताप सिंह जिला महासचिव। **सुकमा** - धनीराम बारसे जिलाध्यक्ष, संजय सोढ़ी जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा। **कोंडागांव** - जसकेतु उसेंडी पार्षद नगर परिषद। **कांकेर** - देवलाल दुग्गा पूर्व विधायक व भरत मटियारा जिला प्रभारी नारायणपुर।

भाजयुमो अध्यक्ष ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का किया दावा

रायपुर। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सूर्या कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय में परिवर्तन उदघोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं।

एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए सूर्या ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में जल्द भाजपा की सरकार बनेगी। सूर्या ने बताया कि इससे पहले छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सीएम हाउस का घेराव किया गया था लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की भाजपा को सीएम हाउस के अंदर पहुंचाएंगे।

सूर्या ने कहा कि सीजीपीएससी

घोटाले को लेकर भाजयुमो हमेशा छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ है। इसी का प्रतिफल है कि सीजीपीएससी मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सूर्या ने कहा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक सरकार को अपनी पीएससी सिस्टम में बदलाव लाने का आदेश मिला है। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं की जीत है। भाजयुमो की जीत है।

इस्रायल मुद्दे पर सूर्या ने कहा कि इस्रायल में जो हो रहा है वह अमानवीय है। वहां छोटे छोटे बच्चों, हजारों लोगों पर बर्बर तरीके से अटैक किया गया। हमास एक आतंकवादी संगठन है। लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस की तरह ही एक आतंकवादी संगठन है। पूरे विश्व को एकजुट होकर हमास का खंडन करना जरूरी है। हमास के खिलाफ जब पूरा विश्व एकजुट है लेकिन कांग्रेस अपनी सीड्ब्ल्यूसी की बैठक में हमास के खिलाफ किसी तरह की बात नहीं कर रहा है।

भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसका आक्रोश आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दिखेगा। युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं के लिए पांच साल से काम कर रही है। युवाओं के लिए एक कार्यशाला भी रखी गई है। इस कार्यशाला में आने वाले चुनाव के लिए युवा मोर्चा की भूमिका तय की जाएगी। हर बूथ को युवा मोर्चा मजबूत करेगी।

पीएससी घोटाले पर हाईकोर्ट का स्टे यहां के युवाओं की जीत है - तेजस्वी

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने एक दिवसीय प्रवास पर बुधवार को राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां माना विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले पर बिलासपुर हाईकोर्ट का स्टे यहां के युवाओं की जीत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जजमेंट से देश के हर राज्य चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक की पीएससी को अपने सिस्टम में रिफार्म करने का अवसर मिला है। युवा मोर्चा शुरू से ही पीएससी की गड़बड़ी को उजागर करता रहा है। यह प्रदेश के युवाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दौरे सीएम हाउस घेराव के लिए किया था आज भाजपा को सीएम हाउस में प्रतिष्ठापित करने के लिए है।

आतंकवाद के प्रति कांग्रेस के नरम होते रुख के कारण

नीरज कुमार दुबे

इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भारत में कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ फिलस्तीन का। फर्क यह है कि जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वह सड़कों पर नहीं उतर रहे लेकिन जो फिलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वह सड़कों पर उतर कर रैलियां निकाल रहे हैं, प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं और धार्मिक नारेबाजी कर माहौल को उन्मादी बना रहे हैं। ऐसा तब किया जा रहा है जब भारत का आधिकारिक रुख इजराइल के साथ खड़े रहने का है। जो लोग इजराइल पर आतंकवादी हमला करने वाले हमास का साथ दे रहे हैं या उससे सहानुभूति रख रहे हैं उनको समझना होगा कि यह आतंकवाद को शह देने और %आ बैल मुझे मार% की कहावत को चरितार्थ करने के समान है। इसके अलावा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने इजराइल को ''उत्पीड़क'' बताते हुए फलस्तीन के लिए ''स्वतंत्रता'' की मांग करते हुए रैलियां निकालीं, यह तो समझ आता है लेकिन यह समझ से परे है कि देश में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा क्यों नहीं की? देखा जाये तो कांग्रेस ने फलस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्म-सम्मान के साथ जीने के अधिकारों की मांग करके एक तरह से आतंकवाद के साथ खड़े होने का संकेत दे दिया है जिससे वह राजनीतिक रूप से निशाने पर भी आ गयी है। यहां सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इजराइल-हमास संघर्ष पर जो प्रस्ताव पास हुआ कहीं इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहे जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार तो नहीं हैं? सवाल यह भी है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादी हमलों में अपने कई बड़े नेताओं को खोया है वह कहीं देशद्रोह का आरोप झेलने वाले कन्हैया कुमार के बहकावे में आकर तो इस तरह के प्रस्ताव पास नहीं कर रही है? हम कन्हैया कुमार पर सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रभारी हैं। इसी संगठन यानि एनएसयूआई की जामिया इकाई ने फलस्तीन का समर्थन करते हुए क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति को ''आतंकवाद'' बताया था। बाद में विवाद होने पर इस पोस्ट को हटा दिया गया था। कांग्रेस की छात्रा शाखा के हटाए गए पोस्ट में लिखा था, ''इजराइल का फलस्तीन पर सात दशक से कब्जा आतंकवाद है। फलस्तीन को इजराइली यहूदीवादी आतंकवाद से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और लंबे समय से जारी इस संघर्ष का न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।'' इसलिए एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की बदलती विचारधारा के पीछे कन्हैया कुमार ही हैं? हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में ऐसे कई और नेता हैं जो समय-समय पर तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आतंक के साथ खड़े नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह कर बुलाया था। यही नहीं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के दस साल के राज में आतंकवादियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कई छोटे-बड़े शहरों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों को निशाना बना कर सैंकड़ों निर्दोषों की जान ली थी लेकिन सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई थी। बल्कि यूपीए के दौर में सरकार से जुड़े लोगों ने आतंक को भगवा रंग देने का प्रयास कर मुद्दे को नया रूप दे डाला था जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा था। हम आपको याद दिला दें कि वह यूपीए का ही दौर था जब 26/11 हमले के बाद हम दुश्मन को सबक सिखाने की बजाय उसे सिर्फ डोजियर सौंपने में लगे हुए थे, वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का ही दौर था जब तकनीक के मामले में सरकारी एजेंसियों से आगे आतंकवादी थे, वह यूपीए का ही दौर था जब निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बजाय कैमरे लगाने के लिए एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र ही लिखता रहता था।

जातीय जनगणना और कांग्रेस का चरित्र

आलोक कुमार

जाति छोड़ो, बंधन तोड़ो के जरिए सामाजिक समरसता बहाल रखने की राह पर चलती हुई कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद प्रखर समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया का तल्ख विरोध झेला था। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह से बैर मोल लेकर सत्ता का परित्याग करना उचित समझा था। इमरजेंसी विरोधियों के हाथों सत्ता गंवाई। मोरारजी देसाई की सरकार में बनी बीपी मंडल रिपोर्ट को दस वर्षों तक लागू करने से मुंह मोड़े रखा। अब अपने पुरखों के उस फैसले को पलटकर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए जातीय जनगणना की मांग में शामिल होने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने स्थापित चरित्र के उलट वाला यह फैसला सोमवार नौ अक्टूबर को चार घंटों की गहन मंथन और बिहार में जातीय सर्वे के प्रकाशन से माइलेज ले गए नीतीश कुमार की काट के लिए लिया है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की ओर से संयोजक होना चाहते हैं। उनकी पार्टी जेडीयू की मांग है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में भाजपा से मुक़ाबिल रहने के साथ नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एकला चलो की राह की काट पर गंभीरता से पहल कर रही है। इस लिहाज से जाति जनगणना का समर्थन कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र बदलने के निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक उस समय हो रही थी जब भारतीय चुनाव आयोग पांच राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की उद्घोषणा कर रहा था। लिहाजा लोग उम्मीद कर रहे थे कि कार्यसमिति की बैठक में विधानसभा चुनावों के मजबूत उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची हो रही होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव लड़ने वाले दिग्गजों के नाम की घोषणा होगी। लेकिन मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में लंबित उम्मीदवारों की सूची पर फैसले की घोषणा की उम्मीद को टालते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस को नए रंग में रंग देने वाले कार्यसमिति के ऐतिहासिक

फैसले की जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि बदलती कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने के लिए जातिवादी तत्वों से समझौता करने में कोई गुरेज नहीं बरतेगी।

विधानसभा चुनाव वाले तीन बड़े राज्य राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का व्यापक असर है। 2018 के विधानसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों की जनता ने कांग्रेस के हक में मतदान किया था। उससे राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का आंकलन करने वाले चुनावी विश्लेषकों की बड़ी किरकिरी हुई थी। चुनाव वाले तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल और मजबूत फोर्स है। इसलिए कार्यसमिति के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी नए चारित्रिक चेहरे के साथ वजूद की लड़ाई के लिए चुनाव में उतर रही है। अपने स्थापित स्टैंड में अभूतपूर्व बदलाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जातीय सर्वे कराने का फैसला लिया है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चुनावी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने सत्ता में वापसी पर जातीय सर्वे कराने और आबादी के आधार पर लोगों को भागीदारी देने की बात कही है।

जनगणना का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार के पास है। लिहाजा बिहार में जनगणना नहीं बल्कि जातियों का सर्वेक्षण हुआ है। इसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ताजा आरोप है कि बिहार के जातीय सर्वे में चालाकी से लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जाति में कई उपजातियों को शामिल रखकर बड़ा खेल किया गया है। लिहाजा यादव जाति को बिहार में सबसे बड़ी आबादी वाला बता दिया गया है। जबकि ओबीसी व महादलित की श्रेणी में आने वाली कई जातियों को उपजातियों में बांटकर कम आबादी वाला दर्शाया गया है। बिहार को देखकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से जातीय सर्वे करवाने का दवाब का बढ़ना लाजिमी है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में फिर से पांव जमाने की टेंशन है। लोकसभा चुनाव की तैयारी मद्देनजर उसे सपा से मिलने वाली चुनौती का अंदाजा है इसलिए भी जातीय आरक्षण की मांग का चैंपियन बनने की यह नई कोशिश की गई है। जनगणना को जातिवार रखा जाए या नहीं संवैधानिक तौर पर यह निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। इसलिए कांग्रेस कार्यसमिति ने अभी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जनगणना में जातियों का उल्लेख करने की मांग के साथ घेरने का फैसला किया है। आगे यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में मदद कर सकता है।

कांग्रेस के इस फैसले पर पार्टी के दिग्गज नेता मानते हैं कि यह फैसला आजादी के आंदोलन की अगुआ और सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के मूलभूत स्वभाव और चरित्र में आमूलचूल परिवर्तन वाला है। भारतीयों में जातीय विभाजन एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसे गंभीरता से उकेरकर भारत में धर्मांतरण के धंधे को खूब जमाया गया। इसकी समझ की वजह से ही डॉ भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को आरक्षण से वंचित रखने का सुझाव दिया था। क्योंकि बाहरी देशों से आए पंथ और धर्मों में लोगों को इस आश्वासन के साथ परिवर्तित किया गया कि उनका धर्म समतामूलक है और उनके यहां जाति और वर्ण के नाम पर कोई विभेद वाली नहीं है। विभेदकारी व्यवस्था के नहीं होने से धर्मांतरित लोगों को समान अवसर मिलता है। इसलिए गैर भारतीय धर्मावालियों को किसी समाजिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मगर वोट की राजनीति ने सब घालमेल कर रखा है।

भारतीयों में समय के साथ जाति और वर्ण विभेद की खाई को भरने की कोशिश को सतत जारी रखने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आरंभ से शालीनता के साथ समाजिक समरसता और अंतरजातीय एकता की पैरोकार रही है। इसके लिए कांग्रेस के धुरंधर नेताओं ने समाज को क्षेत्रवाद और जाति तोड़ो आंदोलन के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इसके लिए आज़ादी के आंदोलन के बाद से ही प्रतीक पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में आज के इस मिश्रित आबादी वाले कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के दौर में कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी जातीय संकीर्णता को बढ़ावा देने पर उतर आती है, तो समझना चाहिए कि वह किस तरह के राजनीतिक मुसीबत में फंसी है, और मुसीबत से उबरने के लिए कोई भी राह चलने को तैयार है। कांग्रेस के इस नए कैरेक्टर को लोग कैसे लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सवाल यह भी है कि क्या इस फैसले से हाशिए पर फंसी कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया उबर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के आवेग में फंसी कांग्रेस पार्टी के हिस्से एक बार फिर माया मिली न राम वाली नौबत हो जायेगी?

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-13)

गतांक से आगे...

जैसे रत्न के इच्छारहित होकर पड़े रहने पर भी मनुष्य उसकी तरफ आकृष्ट होते ही हैं, वैसे ही मात्र सत्तारूप में विद्यमान परमात्म तत्त्व की ओर भी सम्पूर्ण विश्व आकृष्ट होता है। अतः हे पुत्र। इस आत्मा में ही कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व दोनों ही स्थित हैं। कामनाविहीन रहने पर ही आत्मा अकर्ता है और सन्निधि मात्र से वह कर्त्ता बन जाता है। हे मुने! कर्तृत्व एवं अकर्तृत्व इन दोनों का ही निवास अविनाशी परमात्मा में है। तुम्हें यह चमत्कार जिसमें भी परिलक्षित हो, उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं नित्य ही अकर्ता हूँ ऐसी भावना करने पर केवल परमअमृत नामक सत्ता ही शेष रह जाती है।

अतः हे निदाघ! जो प्राणी सत्त्व में स्थित होकर इस लोक में प्रकट हुए हैं, वे ही महान् गुणवान् हैं। वे ही सदा उन्नतिशील होते हुए आकाश में स्थित चन्द्रमा के समान हर्षित होते रहते हैं। सत्त्वगुण में स्थित मनुष्य स्वर्णिम कमल की भाँति रात्रिकाल रूप आपत्तियों में कुम्हलाते नहीं हैं। वे प्राप्त भोगों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते, वरन् शास्त्रोक्त मार्ग में ही भ्रमण करते रहते हैं। वे स्वतः अपने मन के अनुकूल रहकर ही मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित होते रहते हैं।

हे सौम्य ! वे समान भाव में रहते हुए सतत साधु वृत्ति में एकरस बने रहते हैं। मर्यादा से परे होकर भी वे समुद्र के समान विशाल हृदय वाले हो जाते हैं। वे भगवान् भास्कर की भाँति अपने नियत पथ पर हमेशा गमन करते रहते हैं।

प्राज्ञों, संतजनों के साथ प्रयत्नपूर्वक यह चिन्तन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ? यह विराट् विश्व-प्रपञ्च किस प्रकार प्रादुर्भूत हुआ? कभी निरर्थक कार्यों में न लगा रहे तथा अनार्य पुरुष के संग से सदैव अपने को बचाता रहे। सभी की संघारक, मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से न देखे। यदि उपेक्षा करनी ही है, तो शरीर, अस्थि, मांस एवं रक्त आदि को घृणास्पद जानकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार मोती की लड़ियों में सूत्र पिरोया जाता है, उसी प्रकार प्राणियों में पिरोये हुए परमपिता परमात्मा पर ही दृष्टि रखे। उपयोगी वस्तु की ओर भागना एवं अनुपयोगी वस्तु का सदैव के लिए त्याग कर देना ही मन का स्वभाव है। वह बाह्य है, आन्तरिक नहीं, इसे जानना चाहिए।

परमात्मतत्त्व के विषय में गुरु एवं शास्त्र के अनुसार बताये हुए मार्ग से तथा स्वानुभूति से मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जानकर शोक रहित हो जाए। ऐसी अवस्था में खड्ग जैसा कठोर आघात, कमल के कोमल आघात के सदृश तथा अग्नि द्वारा दग्ध किये जाने का प्रभाव, शीतल जल में स्नान करने की भाँति सहन करने योग्य हो जाता है। आग के दहकते अंगारों पर लेटना, चन्दन के लेप के समान शीतल प्रतीत होता है।

क्रमशः ...

राजनीति की जटिलता को भलीभांति समझती थीं विजयराजे सिंधिया

अंकित सिंह

जब भी भाजपा के इतिहास का जिक्र होगा उसमें ग्वालियर पर राज करने वाली राजमाता विजयाराजे सिंधिया का नाम जरूर आएगा। विजयराजे सिंधिया भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उन्हें राजमाता के ही नाम से जाना जाता था। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता की वह मिसाल थीं। राजघराने से ताल्लुक रखने के साथ-साथ राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ रही। विजय राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। विजय राजे सिंधिया का प्रभाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। वह कई दशकों तक जनसंघ की सदस्य रहीं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक भी रहीं।

विजय राजे सिंधिया अपने आप में भारतीय राजनीति में बेहद ही ताकतवर स्थान रखते थीं। राजनीति की जटिलता को भलीभांति समझती थीं और समय-समय पर इसका प्रदर्शन भी करती थीं। भारतीय राजनीति में उनका नाम उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया था जब उन्होंने मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा की सरकार को गिराया था और जनसंघ के विधायकों के समर्थन से स्वर्गीय गोविंद नारायण चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया था। वह ऐसा वक्त था जब लोगों को राजमाता की

राजनीतिक ताकत का एहसास होने लगा था। इसके साथ ही विजय राजे सिंधिया जनसंघ के साथ हो गईं और उसके बाद से लगातार अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से चर्चा कर पार्टी को आगे बढ़ाने लगीं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे से राजमाता सिंधिया का बहुत बड़ा लगाव था। वह उन्हें पुत्रवत मानती थीं।

जनसंघ के नेता के कारण राजमाता सिंधिया ने पूरे देश का दौरा किया और पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। उस दौरान भारतीय जनसंघ को एक सशक्त महिला के तौर पर बेहद ही दमदार नेत्री के रुप में वह मिली थीं। माना जाता है कि भाजपा के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में राजमाता सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान था। जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कराया था। उस दौरान उन्होंने राजमाता को बुलाया था और उनसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने को कहा था। हालांकि, राजमाता ने अपनी दृढ़ता का परिचय देते हुए इंदिरा के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं जनसंघ की विचारधारा को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं जेल जाना पसंद करूंगी लेकिन आपातकाल जैसे काले कानून का कभी समर्थन नहीं करूंगी। विचारधारा के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता शायद ही किसी में देखने को मिलती है। राजमाता जेल गईं लेकिन इंदिरा के सामने नहीं झुकीं। स्वयं राजमाता के बेटे माधव राज सिंधिया देश छोड़कर चले गए थे लेकिन विजय राजे सिंधिया अपनी हिम्मत पर डटी रहीं।

जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर के आग्रह पर जनता पार्टी की ओर से राजमाता सिंधिया ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। भले ही वह हार गईं लेकिन उन्होंने संगठन के निर्णय को किसी विरोध के बिना शिरोधार्य किया। जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें तत्कालीन नेताओं की ओर से अनेक प्रकार के सरकारी पद दिए जाने की बात कही गई। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वह सदैव संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते रहीं। धीरे-धीरे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ती चली गईं। राजमाता वात्सल्य की धनि थीं। वह ममतामई थीं और यही कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को उनका स्नेह सदैव प्राप्त होता रहा। विजया राजे 1957 में पहली बार राजनीति में आई थीं और उन्होंने गुना से चुनाव लड़ा था।

चुनाव में हिंदुत्व के मुकाबले जाति, किसकी होगी जीत

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

आम चुनाव अगले साल की शुरुआत में हैं, लेकिन उससे पहले पांच राज्यों ङ्क मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम- के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। नवंबर में होने जा रहे इन चुनावों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। लगता है कि आजादी के बाद पहली बार यह चुनावी जंग लगभग पूरी तरह जाति पर केंद्रित होगी। इंडिया गठबंधन ने जाति की राजनीति पर बड़ा दांव खेला है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने आर्थिक-सामाजिक सर्वे और जाति जनगणना कराकर भी उसके आंकड़े ठंडे बस्ते में डाल रखा है। जाति जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63 फीसदी है जिसमें 27.12 फीसदी पिछड़ा वर्ग और 36.01 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग है। दलितों की संख्या 19.65 फीसदी, सामान्य वर्ग 15.52 फीसदी और आदिवासी 1.68 फीसदी हैं।

इस जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस रिपोर्ट से गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और अब केंद्र सरकार को यह काम देशभर में करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सोमवार को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद देशव्यापी कास्ट सर्वे कराने की मांग रखी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा है कि विकास विरोधी लोग आज भी जात-पात के नाम पर देश को बांट रहे हैं। दूसरी ओर, राहुल

गांधी ने जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक का नारा दिया है। गौर करने की बात है कि जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तभी से वह राजनीति को जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति की वजह से उसकी लगातार हार हो रही है। यही वजह है कि जातीय जनगणना कराने के साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा का प्रावधान जोड़ने की मांग उसने की है। सच है कि भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति के जरिये पिछड़ी जातियों को काफी हद तक साध लिया है। वहीं, विपक्षी पार्टियां भाजपा के वर्चस्व को तोड़ने के लिए 34 साल पुराने मंडल हथियार का नए सिरे से सहारा ले रही हैं। हालांकि इसे लेकर इंडिया गठबंधन की अपनी परेशानियां भी हैं।

इसकी बेंगलुरु की बैठक में देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठी थी, लेकिन मुंबई बैठक में इस पर मतभेद उभरे तो इसे राजनीतिक प्रस्ताव से हटा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव) ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तय किया गया कि इस पर समन्वय समिति सभी सहयोगी दलों से बातचीत करके रास्ता निकालेगी। 2011 की यूपीए सरकार के दौरान जाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वे हुआ था, लेकिन उसे तकनीकी कारण बताकर सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्नाटक में भी सिद्दारमैया सरकार अपने पिछले कार्यकाल में ही जातीय जनगणना करवा चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है।

विपक्ष की मांग है कि 2011 के सर्वे को प्रकाशित किया जाए या फिर से पूरे देश में जाति जनगणना की जाए। मकसद है जाति के आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग उठाई जाए। राहुल गांधी ने इसी रणनीति के तहत संसद में महिला बिल पर बहस के दौरान केंद्र के विभिन्न विभागों के कुल 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी होने का मुद्दा उठाकर माहौल गरम कर दिया। इसके जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी आंकड़ों की झड़ी लगा दी। मोदी कैबिनेट में 29 मंत्री ओबीसी समूह से आते हैं। भाजपा के 29 फीसदी यानी 85 सांसद ओबीसी हैं। पार्टी के कुल 1358 विधायकों में से 365 यानी 27 फीसदी ओबीसी के हैं। उसके 163 एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य हैं जिनमें 65 ओबीसी हैं। उनकी बातों का मतलब यह था कि हिंदुत्व की राजनीति में ओबीसी की खास जगह है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं। उसकी रणनीति इसी से समझी जा सकती है कि भाजपा के तमाम पैंतरों के जवाब में वह एक से एक नए मुद्दे उठाकर राजनीति को जाति की पटरी पर लाने का प्रयास जारी रखे हुए है।

ध्यान रहे, 2014 के पहले भाजपा को लोकसभा में कभी बहुमत नहीं मिला था। सत्ता की चाहत में उसने बड़ा कार्ड खेला। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत उनकी हिंदुत्व समर्थक छवि थी, लेकिन यह तथ्य भी अपनी जगह था ही कि वह ओबीसी समुदाय के हैं। भाजपा का यह कार्ड ऐसा चला कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, तमाम विधानसभा चुनावों में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को सवर्णों का 61 फीसदी, ओबीसी का 58 फीसदी, आदिवासियों का 49 फीसदी, दलितों का 41 फीसदी और मुस्लिमों का 10 फीसदी वोट मिला था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी नेताओं को सरकार, संगठन में भी अहमियत दी जा रही है।

जाहिर तौर पर मोदी सरकार की पहल ने विपक्षी खेमों का गणित खराब कर दिया है। धर्म और जाति के इस मिले-जुले समीकरण को काटने के लिए विपक्ष अब कास्ट सर्वे का ऐसा मुद्दा लाया है, जो ओबीसी वोटरों तक उसकी सीधी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन सवाल है कि जो पार्टियां एक परिवार और एक जाति में फंस गई हैं क्या वे सारी ओबीसी जातियों में पैठ बना पाएंगी? क्या ये पार्टियां टिकट बंटवारे के दौरान ओबीसी की सारी जातियों और ओबीसी महिलाओं को तरजीह दे पाएंगी? इसका जवाब अगले चुनावों के दौरान ही मिलेगा। कास्ट सर्वे के असर की सीमाएं भी उसी से स्पष्ट होगी।

हिन्द स्वराज्य

सत्याग्रह-आत्मबल (भाग-4)

गतांक से आगे...

प्रश्न- तब तो आप कानून के खिलाफ होते हैं! यह बेवफाई कही जायेगी। हमारी गिनती हमेशा कानून को मानने वाली प्रजा में होती है। आप तो एक्स्ट्रीमिस्ट से भी आगे बढ़ते दीखते हैं। एक्स्ट्रीमिस्ट कहता है कि जो कानून बन चुके हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए; लेकिन कानून खराब हों तो उनके बनाने वालों को मारकर भगा देना चाहिए।

उत्तर- मैं आगे बढ़ता हूँ या पीछे रहता हूँ, इसकी परवाह न आपको होनी चाहिए, न मुझे। हम तो जो अच्छा है उसे खोजना चाहते हैं और उसके मुताबिक बरतना चाहते हैं। हम कानून को मानने वाली प्रजा हैं, इसका सही अर्थ तो यह है कि हम सत्याग्रही प्रजा हैं। कानून जब पसंद न आयें तब हम कानून बनाने वालों का सिर नहीं तोड़ते, बल्कि उन्हें रद कराने के लिए खुद उपवास करते हैं— खुद दुख उठाते हैं। हमें अच्छे या बुरे कानून को मानना चाहिए, ऐसा अर्थ तो आजकल का है। पहले ऐसा नहीं था। तब चाहे जिस कानून को लोग तोड़ते थे और उसकी सजा भोगते थे। FIRE कानून हमें पसंद न हों तो भी उनके मुताबिक चलना चाहिए, यह सिखावन मर्दानगी के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और गुलामी की हद है। सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचें। तो क्या हम नाचेंगे? अगर मैं सत्याग्रही होऊँ तो सरकार से कहूँगा- यह कानून आप अपने घर में रखिये। मैं न तो आपके सामने नंगा होने वाला हूँ और न नाचने वाला हूँ। लेकिन हम ऐसे असत्याग्रही हो गये हैं कि सरकार के जुल्म के सामने झुककर नंगे होकर नाचने से भी ज्यादा नीच काम करते हैं। जिस आदमी में सच्ची इन्सानियत है, जो खुदा से ही डरता है, वह और किसी से नहीं डरेगा। दूसरे के बनाये हुए कानून उसके लिए बंधनकारक नहीं होते। बेचारी सरकार भी नहीं कहती कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा होगी। हम अपनी अधम दशा के कारण मान लेते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, यह हमारा फर्ज है, यह हमारा धर्म है।

क्रमशः ...

राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्यप्रदेश में कौन-से मुद्दे चुनावों में रहेंगे हावी

नीरज कुमार दुबे

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही अब सबकी निगाह इस बात पर लग गयी है कि सत्ता का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? सवाल यह भी है कि क्या जो सेमीफाइनल जीतेगा वही लोकसभा चुनाव भी जीतेगा? हम आपको बता दें कि जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें कांग्रेस के पास दो राज्यों- छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार है तो वहीं भाजपा के पास मध्य प्रदेश में सरकार है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी लेकिन आंतरिक मतभेदों के चलते कमल नाथ की सरकार गिर गयी थी और कांग्रेस विधायकों के दल बदल के चलते शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गये थे। इसके अलावा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है तो वहीं मिजोरम में क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। बहरहाल, चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन देखना होगा कि जनता के मन में क्या है। आइये राज्यवार राजनीतिक हालात, मुद्दों और विभिन्न पार्टियों के समक्ष उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं-

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 के बीच 15 वर्षों तक शासन करने वाली भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के पास वर्तमान में 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 71 सीटें हैं। पार्टी ने आगामी चुनावों में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार की किसान समर्थक, आदिवासी समर्थक और गरीब समर्थक योजनाओं के दम पर 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सत्ताधारी दल मुख्यमंत्री बघेल की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश में है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ग्रामीण मतदाताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ताकत के बारे में बात करें तो देखने को मिलता है कि राजीव गांधी किसान न्याय और गोधन न्याय योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता के अलावा समर्थन मूल्य पर बाजरा तथा विभिन्न वन उपज की खरीद कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय लोगों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए अपनी छवि 'माटी पुत्र' के रूप में विकसित की है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ग्रामीण मतदाताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में पार्टी ने बूथ स्तर तक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। राजीव युवा मितान क्लब योजना से जुड़े करीब तीन लाख युवा, मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में पार्टी की मदद कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ना, नेतृत्व कौशल विकसित करना और उन्हें उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। कांग्रेस ने 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी और राज्य में अपनी मजबूत स्थिति का अहसास कराया था।

इसके अलावा, कांग्रेस की कमजोरियों की बात करें तो आपको बता दें कि पार्टी की राज्य इकाई में गुटबाजी और अंदरुनी कलह है। पिछले पांच वर्षों में, पार्टी में मुख्यमंत्री बघेल के धुर विरोधी टी.एस. सिंहदेव ने कई बार विद्रोह का झंडा उठाया है। आखिरकार पार्टी को इस साल की शुरुआत में उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त करके संतुष्ट करना पड़ा। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के भी बघेल के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि, कुछ महीने पहले ही उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इन सबके बावजूद पार्टी में अंदरूनी कलह अभी भी बरकरार बताई जाती है। भूपेश बघेल सरकार राज्य में कोयला परिवहन, शराब बिक्री, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) कोष के उपयोग और लोक सेवा आयोग भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। वर्तमान शासन के दौरान राज्य में धर्मांतरण, सांप्रदायिक हिंसा और झड़पों की कुछ घटनाएं हुईं, जिससे विपक्षी दल भाजपा को कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाने का मौका मिला।

कांग्रेस के पास अवसरों की बात करें तो आपको बता दें कि पिछले लगभग पांच वर्षों में भाजपा कांग्रेस पर प्रभावी हमला करने में विफल रही है। भाजपा में नेतृत्व का मुद्दा लगातार बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को तीन बार बदला है और पिछले वर्ष विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया है। भाजपा ने रमन सिंह को भी लगभग दरकिनार कर दिया है, जो 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में सरकार पर नागरिक आपूर्ति घोटाले और चिट फंड घोटाले का आरोप लगा। राज्य में कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है और दावा कर रही है कि उसके केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेताओं पर भरोसा नहीं है।

कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे जा सकते हैं अगर उसकी बात करें तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अधूरे वादे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों के क्रोध का कारण बन सकते हैं। 'मोदी फैक्टर' जो भाजपा को प्रतिद्वंद्वी पार्टियों पर बढ़त दिलाता है। आम आदमी पार्टी (आप) और सर्व आदिवासी समाज (आदिवासी संगठनों का एक समूह) के चुनाव में ताल ठोंकने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2018 में चुने गए 68 कांग्रेस विधायकों में से कुल 35 पहली बार चुने गए थे और उनमें से अधिकांश अब अपने प्रदर्शन को लेकर जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबसे प्रमुख राजनीतिक दल माने जाते हैं। राज्य में कुछ अन्य राजनीतिक दल भी हैं लेकिन उनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। आदिवासी समुदायों की संस्था 'सर्व आदिवासी समाज' के चुनाव मैदान में आने से इस बार का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सत्ताधारी दल को नुकसान हो सकता है। राज्य में आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) भी चुनाव मैदान में है। हम आपको बता दें कि राज्य की आबादी में लगभग 32 प्रतिशत हिस्सेदारी जनजातीय समुदाय की है।

दूसरी ओर राज्य में भाजपा की बात करें तो आपको बता दें कि पार्टी अब चुनावी रणनीति के तहत सरकार को भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक राज्य में अपनी यात्राओं के दौरान कई मुद्दों, विशेषकर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर खुलकर हमले कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तक भाजपा की राज्य इकाई जो गुटबाजी से ग्रस्त दिखाई दे रही थी पिछले कुछ महीनों में आक्रामक हो गई है। राज्य में चुनाव के करीब आते ही भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने यहां कई बैठकें की है तथा प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में अच्छी भीड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। पिछले तीन महीनों में अपनी चार रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोयला, शराब, गोबर खरीद और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उपयोग सहित हर क्षेत्र और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार तथा कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के सत्ता में आने पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) में कथित घोटाले की जांच कराने का भी वादा किया है। इधर, भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण हो रहा है तथा दावा किया कि सरकार उन पर अंकुश लगाने में विफल रही है। राज्य में भाजपा ने अब तक 21 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दोनों प्रमुख दलों ने कहा है कि वे सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, न कि किसी एक राजनेता के चेहरे पर।

हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 68 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा स्थापित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को पांच सीटें मिली थीं और उसकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 2018 में 43.04 प्रतिशत मत मिले थे, जो भाजपा (32.97 प्रतिशत) से लगभग 10 प्रतिशत अधिक था।

राजस्थान

सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से लेकर कानून व्यवस्था सहित अनेक मुद्दे हैं जो राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुख कारक बन सकते हैं। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में फिर बाजी मारने के लिए पिछले कुछ महीने से कड़ी मेहनत की है और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने सहित आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले जातिगत सर्वेक्षण कराने का दांव भी चला। राज्य में एक ही चरण में 23 नवंबर को मतदान होगा जबकि वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।

राजस्थान में यह प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं-

सत्ता विरोधी लहर- राज्य में 1993 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद का इतिहास कहता है कि उसके बाद हर विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा को सत्ता की बागडोर मिलती रही है। यानी कोई भी पार्टी लगातार दो बार सरकार नहीं बना पाई। इस परिपाटी के लिहाज से इस बार सत्ता में आने की बारी भाजपा की है।

गुटबाजी- चुनावों से पहले, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने मतभेदों को कम से कम फौरी तौर भले ही दरकिनान कर दिया हो लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए उनका संघर्ष वर्षों से राजस्थान में पार्टी को कमजोर कर रहा है। अगर भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके प्रति वफादार नेताओं को नजरअंदाज करेगी तो उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

ओपीएस, सामाजिक कल्याण योजनाएं- कांग्रेस का चुनाव अभियान राज्य में अपनी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने पर जोर देगा। ओपीएस बहाली का फायदा राज्य के लगभग सात लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा गहलोत की कुछ चर्चित कल्याणकारी योजनाओं में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपये का बीमा, शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा के रूप में 1,000 रुपये की पेंशन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए केवल 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं।

कानून और व्यवस्था- कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा हाल ही में राज्य सरकार पर काफी आक्रामक रही है। भाजपा विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को मुद्दा बना रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार का कहना है कि जब भी ऐसी कोई घटना हुई उसने त्वरित कार्रवाई की।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना- कांग्रेस ने बार-बार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। इस योजना का उद्देश्य 13 जिलों की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करना है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पिछले चुनावों से पहले ईआरसीपी पर दिए गए आश्वासन से पीछे हट गई है। और वह इसी क्षेत्र से अपना चुनावी अभियान शुरू करने की योजना बना रही है।

सांप्रदायिक तनाव- भाजपा ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में सांप्रदायिक दंगों का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या मुद्दा उठाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित रही है।

पेपर लीक- हाल के महीनों में शिक्षकों के लिए रीट जैसी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। यह लाखों बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। भाजपा के अलावा कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट ने भी इसे लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा।

कृषि ऋण माफी- भाजपा ने कांग्रेस पर ऋण माफी का चुनावी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि उसने सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण माफ कर दिए हैं, और अब यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह वाणिज्यिक बैंकों से किसानों का बकाया माफ कराए।

शिक्षकों के तबादले- तृतीय श्रेणी के लगभग एक लाख शिक्षक अपनी पसंद के जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार कहती रही कि वह इस पर एक नीति लाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी लड़ाई

राजस्थान में पिछले लगभग तीन दशक से हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की परिपाटी है और यहां एक बार फिर सत्तारुढ़ कांग्रेस व विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला रहने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले महीने कहा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मुकाबला बहुत करीबी रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि वह राजस्थान में अपनी पार्टी के दोबारा सरकार बनाने को लेकर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आश्वस्त नहीं हैं। राज्य की परिपाटी को देखते हुए हो सकता है कि कांग्रेस नेता का यह आकलन सही साबित हो।

राज्य में 1993 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद का इतिहास कहता है कि उसके बाद हर विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा को सत्ता की बागडोर मिलती रही है। यानी कोई भी पार्टी लगातार दो बार सरकार नहीं बना पाई। इस परिपाटी के लिहाज से इस बार सत्ता में आने की बारी भाजपा की है। यह समीकरण उस समय बन रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य में डबल इंजिन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं ताकि केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो और विकास को गति दी जा सके। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार राज्य का रिवाज टूटेगा। यानी एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि पहली बार राज्य में सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर देखने को नहीं मिली है। गहलोत पिछले कई महीनों से लगातार एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर काम पर जुटे हैं। वे बार बार दावा करते हैं कि उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के हर गांव, हर परिवार तक पहुंचा।

गहलोत की कुछ चर्चित कल्याणकारी योजनाओं में 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' के तहत 25 लाख रुपये का बीमा, 'शहरी रोजगार गारंटी योजना', सामाजिक सुरक्षा के रूप में 1,000 रुपये की पेंशन और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए केवल 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और योजनाओं को पूरा करने के गारंटी कार्ड दिए।

वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का बड़ा दांव चला। यदि सरकारी कर्मियों के परिवारों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लगभग 35 लाख लोगों को लाभ होगा। वहीं चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्होंने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया।

अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पेश करने के अलावा कांग्रेस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को एक प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। पार्टी केंद्र पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अपना वादा नहीं निभाने का आरोप लगा रही है। गहलोत आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान लगातार चलती रही है। मुख्यमंत्री गहलोत व उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच राज्य में नेतृत्व को लेकर तनातनी कम होती नजर नहीं आ रही है। पायलट ने 2020 में पार्टी के दिग्गज गहलोत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। और इसी साल, पायलट ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में सरकार की विफलता को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर भी कांग्रेस सरकार को नहीं बख्शा। यह ऐसा मुद्दा था जिसे मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी भुनाने का प्रयास कर रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं में एक तरह का संघर्ष विराम तो करवा दिया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह शांति पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चुनने के समय भी जारी रहेगी।

उधर भारतीय जनत पार्टी के हालात भी कोई अच्छे नहीं दिखते। पार्टी आलाकमान राज्य में किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से भले ही बच रहा है लेकिर वसुंधरा राजे के समर्थक उन्हें फिर से इस पद के प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। राजे दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। भाजपा के अब तक के प्रचार अभियान में अगर कोई एक चेहरा रहा है तो वह वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। वह पहले ही राज्य में कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, जिनमें से एक तो हाल ही में गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर में हुई। मोदी ने इस जनसभा में पिछले साल जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है।

राज्य में भाजपा की चुनाव रणनीति में तुष्टिकरण और हिंदुत्व अपील प्रमुख कारक हो सकता है। भाजपा कानून-व्यवस्था, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधती रही है। और फिर कथित लाल डायरी का मामला है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें वित्तीय अनियमितताओं का विवरण था। गहलोत मंत्रिमंडल के बर्खास्त सदस्य राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि यह उनके पास है। राज्य के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) द्वार भी कुछ सीटों उम्मीदवार खड़े करने की उम्मीद है।

लेकिन इतिहास के हवाले से विश्लेषक मानते हैं कि राजस्थान के विधानभा चुनाव दरअसल दो ही पार्टियों की दौड़ है। 2018 के विधानसभा चुनावों में 199 सीटों में से कांग्रेस को 99 व भाजपा को 73 सीटें मिलीं। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया जो 28 जनवरी को हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 25 में से 24 सीटें मिलीं। बाकी एक सीट उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के पास चली गई।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। नवंबर में 17 तारीख को होने वाले चुनाव में यहां दस मुद्दों के प्रचार परिदृश्य पर हावी होने की संभावना है और ये मुद्दे 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के नतीजे तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मप्र में सत्तारुढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस सत्ता के मुख्य दावेदार बने रहेंगे, हालांकि आम आदमी पार्टी (आप) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे संगठन अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में भारतीय राजनीति की दो दिग्गज पार्टियों (भाजपा और कांग्रेस) के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2018 में आखिरी चुनावों के बाद, राज्य में मार्च 2020 में तब सत्ता परिवर्तन देखने को मिला जब अनुभवी राजनेता कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा सिर्फ 15 महीने तक विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में वापस आ गई। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक की 15 महीने की अवधि को छोड़कर (जब कांग्रेस सत्ता में थी), भाजपा को लगभग चार कार्यकालों की सत्ता-विरोधी लहर से पार पाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस कई मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ लोगों के बीच नाराजगी को भुनाने की कोशिश करेगी।

1. नरेन्द्र मोदी- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रचार परिदृश्य पर हावी रहेंगे और भाजपा के तुरुप का इक्का बने रहेंगे। भाजपा एक और चुनावी जीत हासिल करने के लिए मोदी की शक्तिशाली वाक् कला, राजनीतिक करिश्मा, स्थायी जन अपील और लोकप्रियता पर बहुत अधिक निर्भर करेगा।

2. भ्रष्टाचार/घोटाले- कांग्रेस मौजूदा भाजपा शासन में कथित भ्रष्टाचार को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। विपक्षी दल ने दावा किया है कि जब भाजपा सत्ता में थी तो कर्नाटक में 40 फीसदी कमीशन की सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 50 फीसदी कमीशन की सरकार है। कुछ महीने पहले कांग्रेस ने प्रदेश भर में शिवराज चौहान सरकार पर 50 फीसदी कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए पोस्टर चिपकाए थे। कांग्रेस ने उज्जैन में 'महाकाल लोक' के निर्माण में भी भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भाजपा शासन के 18 साल के दौरान 250 से ज्यादा बड़े घोटाले भी गिनाए हैं। वित्तीय घोटालों की सूची में व्यापमं भर्ती और प्रवेश घोटाला सबसे ऊपर है।

3. सत्ता विरोधी लहर- भाजपा मध्य प्रदेश में 2003 से 15 महीने की अवधि (दिसंबर 2018-मार्च 2020) को छोड़कर सत्ता में है और सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। इन 15 महीनों में कांग्रेस का शासन मप्र में था। भाजपा शासन के सभी वर्षों में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी का चेहरा बने रहे। रणनीति में बदलाव करते हुए, भाजपा ने राज्य में तीन केंद्रीय मंत्रियों और चार संसद सदस्यों को मैदान में उतारा है, इस कदम को चार बार के मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को कुंद करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इतने सारे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है।

4. सिंधिया समर्थकों का भाग्य- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वास्ते अपने सभी प्रमुख समर्थकों के लिए चुनाव टिकट प्राप्त करना एक कठिन काम होगा, जो 2020 में कांग्रेस छोड़कर उनके साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन सभी को समर्पित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की कीमत पर समायोजित करना होगा जो कि निश्चित रूप से नाराजगी पैदा करेगा।

5. अपराध- बढ़ता अपराध ग्राफ, विशेषकर महिलाओं और दलितों और आदिवासियों सहित कमजोर वर्गों के सदस्यों के खिलाफ घटनाएं, मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया। क्षति नियंत्रण के प्रयास में मुख्यमंत्री चौहान ने आदिवासी व्यक्ति के पैर धोए और उससे माफी मांगी।

6. प्रोजेक्ट चीता- मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छह चीतों और तीन शावकों की मौत ने दुनिया के जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर को देश में फिर से लाने के कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुनरुद्धार कार्यक्रम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। संरक्षणवादियों के एक वर्ग ने पूरी परियोजना की कल्पना और कार्यान्वयन के तरीके पर सवाल उठाया है।

7. किसान- राज्य में कृषि संबंधी मुद्दे हमेशा राजनीतिक चर्चा में हावी रहे हैं और सभी दलों ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है। सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। गुणवत्तापूर्ण बीजों की अनुपलब्धता और उर्वरकों की कमी किसानों के लिए प्रमुख चिंता का विषय रही है।

8. बेरोजगारी- युवाओं के बीच बेरोजगारी की उच्च दर एक चुनौती बनी हुई है और मतदाताओं के लिए शीर्ष मुद्दों में से एक है। बेरोजगार युवाओं का दिल जीतने के लिए आप ने सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। दूसरी ओर, भाजपा सरकार युवाओं में कौशल विकसित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रही है।

9. शिक्षा और स्वास्थ्य- दोनों का आम नागरिकों और उनके समग्र कल्याण से गहरा संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए हैं, लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी है, और यदि शिक्षक उपलब्ध हैं, तो छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। इन चुनावों में अस्थायी शिक्षकों का नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा है। छोटे शहरों के अधिकांश अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों, विशेषकर डॉक्टरों की कमी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

10. मुख्यमंत्री चेहरा-जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके अनुभवी नेता कमल नाथ पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हैं, वहीं मुख्यमंत्री चौहान राज्य के नेताओं में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं, इसके बावजूद भाजपा इस मामले पर स्पष्ट नहीं है।

तेलंगाना

माना जा रहा है कि तेलंगाना विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान के दौरान तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) की परीक्षाओं से जुड़े प्रश्नपत्र लीक मामले के अलावा दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के कविता पर लगे आरोपों, बीआरएस सरकार के 'धरणी' भूमि रिकॉर्ड पोर्टल से संबंधित शिकायतों और राज्य सरकार की कथित विफलताओं का मुद्दा छाया रह सकता है। वहीं, बीआरएस मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते विकास और जनकल्याण के अपने 'तेलंगाना मॉडल' को प्रचारित करना जारी रखेगी। देखा जाये तो तेलंगाना में नौकरियों की कमी एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि युवाओं ने नये राज्य में नौकरियां हासिल करने की उम्मीद के साथ अलग प्रदेश के गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आरोप है कि बीआरएस सरकार 'हर परिवार को नौकरी देने का अपना वादा' निभाने में नाकाम रही है। दोनों पार्टियों का दावा है कि बीआरएस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पर्याप्त भर्तियां न करके तेलंगाना के युवाओं को निराश किया है। वे टीएसपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के लिए भी सरकार को कसूरवार ठहरा रही हैं। प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं ने तेलंगाना को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस और भाजपा ने इस साल मार्च और अप्रैल के दौरान बीआरएस सरकार के खिलाफ कई विरोध-प्रदर्शन किए थे। दोनों दलों ने बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए भी बीआरएस सरकार की आलोचना की थी।

इसके अलावा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सत्तारुढ़ पार्टी की विधान परिषद सदस्य और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर लगे आरोपों के संबंध में बीआरएस और भाजपा के बीच एक मौन सहमति है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में कविता से भी पूछताछ की है, जिससे कांग्रेस और भाजपा को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार पर हमला करने का एक हथियार मिल गया। यही नहीं, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली 'धरणी' को लेकर भी बीआरएस सरकार को कांग्रेस और भाजपा की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रच

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 7 व 17 नवंबर को मतदान 3 दिसंबर को नतीजे

केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार (9 अक्टूबर) को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में हो चरण में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि पांचों चुनावी राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हमने 40 दिनों में सभी राज्यों का दौरा किया। इस दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों, केंद्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में (विकलांग) के कुल वोटरों की संख्या 17.34 लाख है। अगर वे मतदान केंद्र पर आकर वोटिंग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर से भी वोटिंग करने की सुविधा दी जाएगी।

राज्य में पिछला चुनाव 2018 में हुआ था

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा के लिए भी चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, जिसका कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। राज्य में पिछला चुनाव साल 2018 में हुआ था।

पिछले विस चुनाव में किसको कितनी सीटें?

छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें पर जीत हासिल करते हुए राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। वहीं, बीजेपी को महज 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा 7 सीटें अन्य के खाते में गई थीं।

छत्तीसगढ़ में बढ़ी राजनीतिक गहमागहमी

बीते कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है और पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां कांग्रेस राज्य में सत्ता दोहराने के लिए कोशिश कर रही है वहीं, बीजेपी अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए काम कर रही है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में बीजेपी, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। सभी पार्टीयां राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए कमर कस चुकी हैं।

अस्तित्व में आने के विस चुनाव की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद यहां अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं. तीन बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला, तो दो बार यहां कांग्रेस की सरकार रही. वर्ष 2018 में पहली बार कांग्रेस की निर्वाचित सरकार यहां सत्ता में आई. अजित जोगी के बाद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के दूसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने. अजित जोगी का कार्यकाल तीन साल का ही रहा. इसके बाद कांग्रेस पार्टी 15 साल तक यहां सत्ता में नहीं लौटी. बीजेपी के डॉ रमन सिंह के नेतृत्व में यहां 15 साल तक सरकार चली. वर्ष 2018 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई. अब छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है. दोनों पार्टियां चाहतीं हैं कि उनकी ही सरकार बने. आइए, आपको छत्तीसगढ़ का चुनावी इतिहास बताते हैं.

2003 में बीजेपी ने 50, बीएसपी ने जीतीं दो सीटें

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को दो सीटों पर जीत मिली थी. इस साल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 50 सीटें जीतीं. कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति को विधानसभा में इंट्री मिली.

बीजेपी ने इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतीं

वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने फिर दो सीट पर जीत दर्ज की. बीजेपी ने 50 सीटें जीतीं और कांग्रेस के हिस्से में 38 सीटें आयीं. इस बार एनसीपी खाली हाथ रही. अजित जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़-जोगी (जेसीसी-जे) का भी खाता नहीं खुला.

2013 में थोड़ा गड़बड़ाया बीजेपी का प्रदर्शन

वर्ष 2013 में बीजेपी की एक सीट घट गयी. बसपा की भी एक सीट घटी. इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बसपा को एक और बीजेपी को 49 सीटों पर जीत मिली. कांग्रेस के 39 उम्मीदवार जीते और विधानसभा पहुंचे. इसी साल पहली बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का खाता खुला. यानी उसका एक उम्मीदवार जीता.

2018 में भूपेश का चला जादू, बदल गई सरकार

वर्ष 2018 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ. कांग्रेस की सीटें डबल हो गयीं. यानी उसे 68 सीट पर जीत मिली. बीजेपी 15 सीट पर सिमट गयी. बसपा को दो सीटों पर जीत मिली और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को पांच सीट पर विजयश्री मिली.

पहली विधानसभा में थे कांग्रेस के 48 सदस्य

वर्ष 2000 में जब प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था, तब विधानसभा में कांग्रेस के 48 और बीजेपी के 36 विधायक थे. बसपा के तीन, निर्दलीय दो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक विधायक सदन में थे. जब सदन का विघटन हुआ, तब कांग्रेस के पास 62, बीजेपी के पास 22, बसपा के पास 2, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सदस्य सदन में थे. एक असंबद्ध और एक नामित सदस्य भी विधानसभा में थे.

दूसरी विस में भाजपा ने बनाई सरकार

द्वितीय विधानसभा में बीजेपी के 50 विधायक जीतकर आये, कांग्रेस के 37, बसपा के दो, एनसीपी के एक उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे. जब सदन का विघटन हुआ, उस वक्त बीजेपी के 52 विधायक थे. कांग्रेस के 34, बसपा के एक, एनसीपी के एक, मनोनीत एक विधायक थे. दो सीट उस वक्त रिक्त थी.

तृतीय विधानसभा में कांग्रेस को मिली 38 सीटें

तृतीय विधानसभा में भी बीजेपी के 50 विधायक थे. कांग्रेस के 38 और बसपा के दो विधायक चुनकर आये थे. जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का विघटन हुआ, तब बीजेपी के सदस्यों की संख्या घटकर 49 हो गयी. कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 38 पर यथावत बनी रही. बसपा के दो, एक निर्दलीय और एक मनोनीत विधायक थे.

चौथी विधानसभा में थे बीजेपी के 49 सदस्य

चतुर्थ विधानसभा के गठन के समय बीजेपी के सदस्यों की संख्या 49 थी, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 38. बसपा, निर्दलीय, मनोनीत एक-एक विधायक सदन में थे. एक सीट रिक्त रह गयी थी.

2018 में कांग्रेस ने जीती 68 सीटें

पंचम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 68 सीटें जीतीं थीं. बीजेपी ने 15, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने पांच और बसपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस वक्त विधानसभा में कांग्रेस के 71 सदस्य हैं, जबकि बीजेपी के सदस्यों की संख्या घटकर 13 रह गयी है. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के भी विधायकों की संख्या घटकर तीन हो गयी. बसपा के दो विधायक कायम हैं।

1952 का पहला विधानसभा चुनाव

20 सीटों से चुने गए थे दो-दो विधायक

छत्तीसगढ़ से विधानसभा और लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में कुछ स्थानों से दो-दो सदस्य चुने जाते थे। भारत के आजाद होने के बाद संविधान के प्रावधान के अनुसार पहली बार लोकसभा और विधानसभा के लिए 1951-52 में चुनाव हुए थे। उस समय छत्तीसगढ़ का क्षेत्र सेंट्रल प्राविंस और बरार को मिलाकर बने तत्कालीन मध्यप्रदेश (नागपुर में राजधानी) का हिस्सा था। उस समय की नागपुर स्थित मध्यप्रदेश की विधानसभा में 1952 में कुल 184 विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर 232 विधायक पहुंचे थे। इन 184 में से 136 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुने गए थे किंतु 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से दो-दो सदस्य चुने गए थे। इन 184 में से 9 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे।

तत्कालीन मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 62 विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें से कुल 82 सदस्य चुने जाते थे। 62 में से 8 क्षेत्र अजजा के लिए आरक्षित थे। 62 में से 42 क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुनकर पहुंचे थे और 20 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक से दो-दो सदस्य चुने गए थे। दो-दो विधायक चुनकर भेजने वाले विधानसभा क्षेत्र थे- मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, पाल, जशपुरनगर, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, सारंगढ़, चंद्रपुर-बिर्रा, जांजगीर-पामगढ़, अकलतरा-मस्तूरी, कटघोरा, मुंगेली, भाटापारा-सीतापुर, कुसमंडी-कसडोल, आरंग-खरोरा, जगदलपुर, कांकेर, बालोद, बोरी-देवकर और बेमेतरा। इन द्विसदस्यीय विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकांश में एक सीट सामान्य और एक सीट आरक्षित (अजा के लिए) होती थी।

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार थे- सामरी, सीतापुर, रामपुर, बीजापुर, सुकमा, चित्रकोट, केसकाल और नारायणपुर। 1952 के चुनाव में केसकाल में राजमन बिना चुनाव लड़े विधायक निर्वाचित हुए थे। इस चुनाव में पंडित रविशंकर शुक्ल सराईपाली से, महंत लक्ष्मीनारायण दास भटगांव से और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से चुने गए थे। निर्दलीय वी. वाय. तामस्कर बेमेतरा से चुने गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को इकतरफा विजय मिली थी फिर भी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के प्रमुख नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर से, खूबचंद बघेल पचेड़ा से, ब्रिजलाल वर्मा कसडोल से तथा जोहन जशपुर नगर से जीते थे। किसान मजदूर प्रजा पार्टी बाद में समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी के रूप में प्रभावशील रही। एक अन्य महत्वपूर्ण दल रामराज्य परिषद को जशपुर नगर, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों से सफलता मिली थी। बाद में रामराज्य परिषद का प्रभाव समाप्त हो गया और फिर जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा। इनके अलावा 15 निर्दलीय भी चुनकर आए थे।

कई रियासतों के राजा भी चुनकर आए थे। इनमें प्रमुख तौर पर राजा नरेशचंद्र सिंह सारंगढ़ से, राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह खैरागढ़ से उनकी पत्नी रानी पद्मावती देवी बोरी देवकर से, सरगुजा के राजा रामानुज शरण सिंह देव अंबिकापुर से, जशपुर राजघराने से विजय भूषणसिंह देव जशपुर नगर से। रायगढ़ के राजा ललित कुमार सिंह घरघोड़ा से, धर्मजयगढ़ से वहां के राजा चंद्रचूड़ प्रसाद सिंहदेव, पंडरिया से पद्म राज सिंह, कांकेर से महाराजा अधिराज बी.पी. देव चुने गए थे। रविशंकर शुक्ल मंत्रिमंडल में वीरेन्द्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती देवी दोनों ही एक साथ मंत्री बने। राजा नरेशचंद्र सिंह तो लगातार मंत्री बनते रहे और 1967 में 14 दिनों के लिए अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। राजा नरेशचंद्र सिंह की बेटियां भी राजनीति में आईं और मंत्री, विधायक तथा सांसद बनीं। इसी तरह खैरागढ़ परिवार के पुत्र और बहुएं लगातार विधायक, मंत्री और सांसद बनते रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में राजपरिवारों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तब लोकसभा के लिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और दुर्ग-बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे। इनमें से बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग लोकसभा से दो-दो संसद सदस्य चुने गए थे, जबकि महासमुंद, दुर्ग और बस्तर से एक-एक सांसद चुने गए थे। यह स्मरणीय है कि तत्कालीन सेंट्रल प्राविंस और बरार से मिलकर बने मध्यप्रदेश में 1919 में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में बरार से एक और शेष प्रदेश से एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था।

देश में आने वाले विधानसभा

चुनाव के पहले महिला आरक्षण बिल पर सुगबुगाहट तेज हो गई है. माना जा रहा है संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया जाएगा.

2008

विधानसभा चुनाव में कुल एक हजार 66 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे इसमें से 972 पुरुष और 94 महिला प्रत्याशी रहीं. चुनाव परिणाम में 11 महिलाएं विधायक बनी इसमें से 6 विधायक बीजेपी की थी बीजेपी और 4 कांग्रेस की प्रत्याशी विधायक बनी.

2018 के विधानसभा चुनाव में 13 महिला प्रत्याशी विधायक बनीं. इसमें से राज्य में 90 में से 16 महिला विधायक है और इसमें से 13 विधायक कांग्रेस पार्टी की है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी साल दर साल बढ़ी

पहली बार 2018 विस चुनाव के बाद 90 सीट में से 16 सीट पर महिलाओं का कब्जा

इसके बाद लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण सीट हो जाएगी. इसकी संख्या कितनी होगी और क्या विधानसभा की सीटों में वृद्धि की जाएगी, इसपर अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं आई है. लेकिन अब तक महिलाओं ने राजनीति में कितनी दमखम दिखाई है, ये आपको छत्तीसगढ़ के हिस्से से बताते हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं. 2003 से छत्तीसगढ़ में विधानसभा हो रहे हैं. 90 विधानसभा सीट है और लगातार 3 बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई लेकिन 2018 में कांग्रेस में निर्वाचित सरकार बनाई. इन विधानसभा चुनाव में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है. छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 90 सीट में से 16 सीट पर महिलाओं का कब्जा हुआ. छत्तीसगढ़ में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी देश के कई राज्यों की तुलना में ज्यादा है.

और 5 विधायक कांग्रेस पार्टी से थीं. इसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव में 986 लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा. इसमें से 901 पुरुष प्रत्याशी थे और 83 महिला प्रत्याशी थी. इसमें से केवल 10 महिला विधानसभा तक पहुंची और इसमें से 6 10 विधायक केवल कांग्रेस पार्टी से बनी. बीजेपी ,जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से 1-1 प्रत्याशी विधायक बनी. इसके अलावा इस 2018 से 2023 के बीच हुए उपचुनाओं में कांग्रेस ने 3 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा और तीनों ही विधानसभा चुनाव जीत गई. इसके बाद अब आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 और बीजेपी ने 12 महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतरा है.

महिला आरक्षण बिल को विपक्ष की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है. क्योंकि कांग्रेस जब केंद्र की सत्ता में रही तब भी महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की गई थी. लेकिन लोकसभा में बिल अटक गई. वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉ. अजय चंद्राकर का इस बिल को लेकर कहना है कि कैबिनेट में मंजूरी मिली है. लेकिन महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा और क्या वर्गवार आरक्षण होगा इसपर कुछ साफ नहीं है. इसलिए इसपर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा. क्योंकि अगर वर्गवार आरक्षण व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो केंद्र सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा. वहीं ये लंबी प्रक्रिया है आने वाले विधानसभा चुनाव में लागू होने की स्थिति नहीं है. यानी छत्तीसगढ़ में 2027-28 के विधानसभा चुनाव में लागू हो सकता है.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

तुष्टिकरण की राजनीति में देशहित का बलिदानः हिमंता

गुवाहाटी। असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने इस्राइल पर हमास के आतंकी हमले की आलोचना नहीं करने के लिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हिमंता बिस्व सरमा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान, तालिबान और कांग्रेस के बयानों में समानता है। असम सीएम ने कांग्रेस और पाकिस्तान के बयान भी साझा किए। असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के प्रस्ताव और पाकिस्तान-तालिबान के बयानों में समानता है। तीनों ने हमास के आतंकी हमले की आलोचना नहीं की है। तीनों ने ही इस्राइल पर आतंकी हमले की बात नहीं मानी है और साथ ही तीनों महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने के मुद्दे पर भी चुप हैं। सरमा ने लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देशहित का बलिदान करना कांग्रेस के डीएनए में है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक हुई थी। इस दौरान प्रस्ताव पास कर मध्य पूर्व में इस्राइल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई की निंदा की गई।

राजस्थान में मतदान की तारीख में बदलाव

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थानविधानसभा चुनाव 2023 में अहम बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख 23 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदान की तारीख में बदलाव विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के अभ्यावेदन और विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में उस दिन बड़े पैमाने पर शादी/सामाजिक जुड़ाव पर विचार करने के बाद उठाए गए मुद्दों के बाद किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती है, विभिन्न तार्किक मुद्दे और मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी कम हो सकती है। राज्य की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 235 नवबंर को मतदान होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा।

सपा नेता आजम खां के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे को अंतरिम राहत देने से बुधवार को इनकार कर दिया है। दरअसल, विरोध प्रदर्शन मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने याचिका में मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत को आदेश दिया जाए कि वह उनके नाबालिग होने के दावे की पुष्टि होने तक उनके खिलाफ कोई फैसला न सुनाएं। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर को मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत अब्दुल्ला आजम खां के नाबालिग होने के पहलू पर फैसला करें और निर्णय को आगे के विचार के लिए उसके पास भेजें। इस आदेश का हवाला देते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ से कहा कि जब तक नाबालिग होने के दावे पर रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट को लंबित आपराधिक मामले में आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा जाए।

के. चंद्रशेखर राव 15 से शुरू करेंगे चुनावी अभियान

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव राज्य विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान चलाएंगे और 41 रैलियों को संबोधित करेंगे जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। बीआरएस ने पहले ही घोषणा की है कि राव 15 अक्टूबर को अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मंगलवार रात को जारी की गयी कार्यक्रम सूची के अनुसार, राव 16 अक्टूबर को जनगांव और भुवनागिरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद 17 अक्टूबर को सिरसिल्ला और सिद्दीपेट में प्रचार करेंगे। वह 18 अक्टूबर को जडचर्ला और मेडचल में दो बैठकों में भाग लेंगे। एक सप्ताह बाद 26 अक्टूबर को वह तीन रैलियां करेंगे और उनका प्रचार अभियान नौ नवंबर तक जारी रहेगा। राव नौ नवंबर को गजवेल और कामारेड्डी दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करेंगे।

आप ने संजय की सुरक्षा पर कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने अदालत को सूचित किए बिना, पार्टी के गिरफ्तार नेता संजय सिंह को कहीं भी न ले जाने के लिए विशेष अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिए जाने का बुधवार को स्वागत किया। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 'आप' विधायक दिलीप पाण्डेय ने सिंह के उन दावों को दोहराया कि प्रवर्तन निदेशालय के कुछ ''गुप्त उद्देश्य'' हैं। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह की ईडी की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान सिंह ने अदालत में कहा, न्यायाधीश ने ईडी से पूछा कि वह सिंह से अपना कार्यालय छोड़ने की अनिच्छा के बारे में लिखित बयान क्यों चाहता है। इस पर, केंद्रीय एजेंसी ने सिंह के आरोप को खारिज किया। न्यायाधीश ने कहा, ''आपको उन्हें अदालत के आदेश के बिना कहीं नहीं ले जाना चाहिए।''

राजस्थान और मध्यप्रदेश में नया विकल्प तलाश रही भाजपा, कांग्रेस को पुराने पर भरोसा!

नईदिल्ली। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा सीधी लड़ाई में आमने-सामने हैं, इसलिए दोनों पक्षों के राज्य नेतृत्व को %बनाओ या बिगाड़ो की लड़ाई% वाली कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए, सुर्खियों में मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत के पुराने नेता होंगे। वहीं, भाजपा की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चार कार्यकाल के बावजूद मध्य प्रदेश में कठिन राह पर चल रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (राजस्थान) और रमन सिंह (छत्तीसगढ़) को दोनों राज्यों में पार्टी की रैली में तस्वीरे दिख तो जाती हैं पर दोनों ही अपने क्षेत्रों में पहले की तरह प्रभावी भूमिका निभाने से कोसों दूर हैं।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस- मध्य प्रदेश में देखें तो कांग्रेस कमलनाथ पर एक बार फिर से दांव लगाने की तैयारी में है। हालांकि, वह इस बार पिछली बार जैसी गलती नहीं करने वाली। इस बार कमलनाथ के साथ-साथ युवा नेताओं को भी महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह पर भी कांग्रेस भरोसा जताती दिखाई दे रही है। हालांकि, दिग्विजय सिंह प्रदेश की राजनीति में तो नहीं लौटने वाले। लेकिन इसका फायदा उनके बेटे को मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के बाद पार्टी में हुई फूट से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। दिल्ली की राजनीति की ओर रुख करने की बजाय कमलनाथ राज्य में बने रहे और अपने अपमान का बदला लेने की इस बार पूरी कोशिश करने वाले हैं।

राजस्थान में कांग्रेस- कांग्रेस के लिए राजस्थान की बात करें तो यहां वह सचिन पायलट की चुनौती से जूझ रही है। सचिन पायलट लगातार अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। अशोक गहलोत के साथ अनबन के बाद सचिन पायलट ने अपना काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वह राज्य में मजबूती के साथ बने रहे। गहलोत के ऊपर दबाव बनाने के लिए वह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चुनौतियां भी पेश करते रहे। दूसरी ओर गहलोत भी अपनी जादूगरी दिखने में पीछे नहीं रहे। राज्य में अपनी भूमिका को बरकरार रखने के लिए उन्होंने लोक लुभावने वायदे किए। साथ ही साथ विधायकों को हमेशा अपने साथ जोड़े

रखा। चुनाव को देखते हुए लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतरने की कोशिश की। गहलोत इस बात को भली-भांति समझते हैं कि अगर सचिन पायलट को आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी और उनके समर्थकों के लिए यह अच्छा नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में भाजपा-भाजपा को यह पता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को किनारे करना इतना आसान नहीं है। यही हाल राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर है। यही कारण है कि भाजपा इन्हें अपने पोस्टर्स में तो रख रही है। लेकिन उनके चेहरे को आगे करने की कोशिश में नहीं है। दोनों ही राज्यों में भाजपा नई पौध को तैयार करने में जुटी हुई है जो पार्टी के भविष्य को राज्य में अच्छे नेतृत्व से संरक्षित कर सके। मध्य प्रदेश में शिवराज के कई विकल्प को तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता शामिल है। हालांकि, शिवराज सिंह चौहान भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चौहान को दरकिनार करने की अटकलें जोरों पर हैं। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले चौहान को हाल ही में सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों के दौरान भावुक होते देखा गया है।

राजस्थान में भाजपा- दूसरी ओर राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को लेकर भी असमंजस की स्थिति में है। उन्हें आगे तो रख रही है। लेकिन उनके विकल्प के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं को आगे कर रही है। बीच-बीच में वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबर भी आ जाती है। इसे शांत करने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन वसुंधरा पर दांव नहीं लगाया जाता।

कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में नए और पुराने का खेल चल रहा है। जनता अपने विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला चुनाव में करेगी। यही तो प्रजातंत्र है।

हरियाणा में किसी भी बिरादरी का मुख्यमंत्री बन सकता है : सैलजा

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 'चार उप मुख्यमंत्री बनाने के वादे' वाले हालिया बयान को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि अब तो बात यह होनी चाहिए कि आलाकमान की स्वीकृति से 36 बिरादरी में से किसी भी बिरादरी का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि यह पद किसी के लिए आरक्षित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने किसी भी व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है कि वह व्यक्तिगत स्तर पर चार उप मुख्यमंत्री बनाने जैसा वादा करे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में ब्राह्मण, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की किसी अन्य जाति से कुल चार उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उनका कहना था कि 2019 के चुनाव में भी ऐसा वादा किया गया था। हुड्डा के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सैलजा ने संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूं कि 2019 में, मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात (चार उप मुख्यमंत्री की) कभी नहीं हुई। पार्टी आलाकमान की तरफ से भी उस वक्त ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। आज भी यह (बयान देने का) कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है?'' उन्होंने कहा, ''हम 36 बिरादरी की पार्टी हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कौन क्या बनेगा, यह आलाकमान का फैसला होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को आलाकमान ने यह अधिकार दिया है कि इस तरह के वादे और बातें करे।''

मोदी कैबिनेट ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को दी मंजूरी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उदेश्य उनकी आकांक्षाओं को साकार करना और सरकार के संपूर्ण दायरे में विकसित भारत का निर्माण करना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात को लेकर जानकारी दी।

मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। नई व्यवस्था के तहत, संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ, युवा समुदाय परिवर्तन एजेंट और राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे, जिससे उन्हें सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। यह राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में, लाभार्थी 10-19 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे।

इन मामलो में मिलेगा बढ़ावा

युवाओं में नेतृत्व विकास। अलग-अलग शारीरिक संपर्क से प्रोग्रामेटिक कौशल में बदलाव करके अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करें। युवाओं को सामाजिक नवप्रवर्तक, समुदायों में नेता बनाने के लिए उनमें अधिक निवेश करना। युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को विकास का सक्रिय चालक बनाना। युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल। मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से दक्षता में वृद्धि। युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करें। एक केंद्रीकृत

युवा डेटा बेस बनाएं। युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दोतरफा संचार में सुधार।एक भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना।

एचईसीआई विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जायेगा : प्रधान

नईदिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन चिकित्सा एवं विधि कॉलेजों को इसके दायरे में नहीं लाया जायेगा। प्रधान ने 'पीटीआई-भाषा' से एक साक्षात्कार में कहा कि एचईसीआई की तीन प्रमुख भूमिकाएं विनियमन, मान्यता और पेशेवर मानक स्थापित करना हैं। मंत्री ने कहा कि वित्त पोषण (फंडिंग) एचईसीआई के अधीन नहीं होगा और वित्त पोषण की स्वायत्तता प्रशासनिक मंत्रालय के पास रहेगी। प्रधान ने कहा, ''हम जल्द ही संसद में एचईसीआई विधेयक लाएंगे... उसके बाद स्थायी समिति की भी जांच होगी लेकिन हमने हर चीज के लिए व्यापक काम शुरू कर दिया है। तीन प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं। पहली भूमिका नियामक की है, जो यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) करता है... इसने पहले ही अपने स्तर पर कई आंतरिक सुधार शुरू कर दिए हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला आज

नईदिल्ली। भारत से हारने के बाद 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 2023 में 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दोनों टीम के बीच 50 ओवर के क्रिकेट में करीबी प्रतिद्वंद्विता है। वनडे वर्ल्ड कप और कुल मिलाकर वनडे में दोनों एक-दूसरे से कड़ी टक्कर देते हैं। वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच आमने-सामने की भिड़ंत का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। दोनों पक्षों ने अपनी 31 साल की एकदिवसीय क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में कुल 108 मैच खेले हैं। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.00 बजे से शुरू होगा। आप इसे स्टार स्पोटर्स और डिजनी हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले दो मैच गंवाने के बाद अगले तीन मैच जीते थे और टीम को इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया को भी दमदार वापसी करने के लिए जाना जाता है और इसलिए यह मुकाबला रोमांचक होने की संभावना है।

टीम इस प्रकार हैं

दक्षिण अफ्रीका- तेम्बा बावुमा (कप्तान), गेराल्ड कोएट्ज़ी, क्विंटन डिकॉक, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एंडिले फेहलुकवायो, कैगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी, रासी वान डेर डुसेन , लिज़ाद विलियम्स।

ऑस्ट्रेलिया- पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा, मिशेल स्टार्क।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 394 अंक चढ़ा, निफ्टी तीन सप्ताह के हाई लेवल पर

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे कारोबारी सेशन में तेजी दर्ज की गई और सेंसेक्स 394 अंक की छलांग के साथ 66,500 अंक के पास पहुंच गया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 393.69 या 0.60 प्रतिशत की बढ़त लेकर 66,473.05 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,592.16 अंक तक पहुंच गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 121.50 अंक या 0.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ 19,811.35 अंक के नोट पर बंद हुआ। कच्चे तेल के प्राइस में स्थिरता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की नरम टिप्पणियों के बाद ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना के कमजोर से पड़ने से भी बाजार को फायदा मिला।

भारत के 2050 तक 30000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद

नईदिल्ली। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष एवं आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बुधवार को कहा कि मजबूत खपत व निर्यात के दम पर भारत के 2050 तक 30000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने इस साल भारत की वृद्धि दर करीब 6.3 प्रतिशत और मुद्रास्फीति करीब छह प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसलिए मौजूदा मूल्य पर जीडीपी करीब 10-12 प्रतिशत होगी। चक्रवर्ती ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, '' अगर इसी तरह की गति कुछ साल तक जारी रही तो भारत 2045-50 तक 30000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और प्रति व्यक्ति आय 21,000 अमेरिकी डॉलर होगी।''

4 करोड़ लोगों ने लगाया म्युचुअल फंड में पैसा

नईदिल्ली। भारत में यूनिक म्युचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या सितंबर महीने में 4 करोड़ यानी 40 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर गई है। पिछले 21 महीनों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 1 करोड़ नए लोगों ने एंट्री की और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या इस साल कुल इनकम टैक्स फाइलिंग की लगभग 57 प्रतिशत है और देश में कुल जितने पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनमें से 6.5 प्रतिशत लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। बता दें कि यूनिक निवेशक संख्या म्युचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ पंजीकृत कुल पेन है। ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो में लगातार बढ़ोतरी के बीच इंडस्ट्री ने यह उपलब्धि हासिल की। सितंबर में इंडस्ट्री ने पहली बार एसआईपी के जरिये 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं। एक्टिव इक्विटी योजनाओं में नेट इनफ्लो, जो रिटेल निवेशकों से बड़ी मात्रा में निवेश प्राप्त करता है, महीने-दर-महीने 30 प्रतिशत गिरकर 14,090 करोड़ रुपये हो गया।

गोयल नमक कंपनी की धमाकेदार एंट्री

नईदिल्ली। कच्चा नमक बनाने और रिफाइन करने वाली कंपनी गोयल साल्ट के शेयरों की आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर धमाकेदार एंट्री हुई। हालांकि 200 फीसदी से ज्यादा का लिस्टिंग गेन देने के बाद भी इसके शेयरों में तेजी टिकी नहीं और ये लिस्टिंग के बाद ही शेयर धड़ाम से नीचे आ गए। आईपीओ के तहत 38 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। बुधवार को एनएसई एसएमई पर इसकी 130 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है यानी कि आईपीओ निवेशकों को 242 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर लुढ़ककर 124 रुपये पर आ गए है यानी कि आईपीओ निवेशक 226 फीसदी मुनाफे में हैं। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 49.02 लाख नए शेयर जारी हुए हैं। गोयल साल्ट का 18.63 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 सितंबर -3 अक्टूबर के बीच खुला था।

डीमैट खातों की संख्या का बढ़ना अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास है

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

शेयर बाजार में जिस तेजी से नए डीमेट खाते खुल रहे हैं वह स्पष्ट रूप से लोगों के विश्वास का ही परिणाम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को आम जन के वित्तीय निवेश को लेकर देखा जा सकता है। देश के शेयर बाजार में लगातार इस मायने में बूम देखा जा रहा है कि चालू कैलेण्डर वर्ष के हर महीने लाखों नए डीमेट खाते खुल रहे हैं। इसी कैलेण्डर वर्ष की बात की जाए तो जनवरी से अब तक दो करोड़ से अधिक नए डीमेट खाते खुले हैं। अकेले सितंबर माह में करीब 30 लाख 60 हजार नए डीमेट खाते अस्तित्व में आये हैं वहीं इससे पहले अगस्त में इस साल के सर्वाधिक 31 लाख नए खाते खुले हैं। इसी तरह से गए महीने 10 आइपीओ बाजार में आए हैं और इनमें निवेशकों ने दिल खोलकर पैसा लगाया है। इन 14 आईपीओ के माध्यम से कंपनियों ने 11868 करोड़ रुपए जुटाये हैं। यदि देखा जाए तो दिसंबर 2010 के बाद सबसे अधिक आईपीओ बाजार में आये हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो इस साल जनवरी से सितंबर तक 34 आइपीओ के माध्यम से कंपनियों ने निवेशकों से 26913 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सभी आइपीओ ओवर सब्सक्राइब रहे हैं। यह सब तो तब है जब आज दुनिया के देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पर यह साफ हो जाता है कि शेयर बाजार में लगातार नए खाते खुलना और आइपीओ को अच्छा समर्थन मिलना इस बात का संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों में किसी तरह का नकारात्मक विचार नहीं है। बल्कि यह कहा जाना उचित होगा कि लोगों का देश की अर्थव्यवस्था व देश के आर्थिक हालातों के प्रति विश्वास कायम है।

दरअसल कोरोना के बाद जिस तरह के

हालात हुए और देश दुनिया की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं उससे लोगों में अर्थव्यवस्था को लेकर अनेक आशंकाएं हुईं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दुनिया के अधिकांश देश आर्थिक संकट के दौर से गुजरे और आज भी गुजर रहे हैं। इसके अलावा पिछले लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध से हालात और खराब हुए हैं। अब इजराइल और हमास के ताजा हमलों से नया संकट सामने आ गया है। इससे सबके साथ ही दुनिया के अधिकांश देशों में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। चीन की नीतियों से दुनिया के देश त्रस्त हैं सो अलग। इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आये दिन आने वाले तूफान, भूकंप आदि घटनाएं दुनिया के देशों में भय का वातावरण बना रही हैं। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, मौसम की बेरूखी आदि को किसी भी हालात में ठीक नहीं माना जा सकता है।

इन सब हालातों के बीच देश की अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों के रुख को दो दृष्टि से समझना होगा। एक और बैंकों में बचत की भावना में गिरावट दर्ज हो रही है। एक समय था जब हमारी परंपरा में बचत को खास महत्व दिया जाता था, आज हालात ठीक विपरीत हैं। बचत की तुलना में वित्तदायी संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी और शेयर बाजार जिसे हमेशा से अस्थिर समझा जाता रहा है और जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सर्वाधिक जोखिम भरा निवेश माना जाता रहा है, वहां देश का मध्यम वर्ग खासतौर से युवा पीढ़ी जोखिम भरे शेयर बाजार में बेहिचक निवेश करने को आगे आ रही है। हालांकि इसके पीछे शेयर बाजार में एक कारण आकर्षक रिटर्न को माना जा रहा है तो दूसरी और अन्य क्षेत्रों में अधिक अस्थिरता भी यहां आने का बड़ा कारण है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि शेयर बाजार सबसे जोखिम भरा है। पर जिस तरह से प्रति माह नित नए डीमेट अकाउंट खोले जा रहे हैं और जिस तरह से आइपीओ को रेस्पांस मिल रहा है, उससे साफ हो जाता है कि आज की पीढ़ी लाख रिस्क होने के बावजूद जोखिम भरे रास्ते को चुन रही है। इससे यह तो माना जा सकता है कि निवेशकों खासतौर से मध्यम वर्ग को शेयर बाजार पर पूरा विश्वास जम रहा है।

हम कार्यकर्ता नहीं बल्कि पार्टी के सैनिक है: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। हम भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं उनकी फौज है। हमें एक सैनिक की तरह चुनावी रण में उतर जाना है। हमें अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराना है।

रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वामन राव लाखे वार्ड, पुरानी बस्ती वार्ड, महामाया पारा वार्ड और संतोषी नगर वार्ड में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। सभी शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उनके बूथ के बारे में विस्तृत जानकारी ली। सभी को बूथ की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि अपने वार्ड के कार्यों के बारे में लोगों को बताएं। हर शक्ति केंद्र के संयोजक, सहसंयोजक को पोलिंग बूथ के अनुसार उतने ही प्रमुख बनाएं। उन्हे 20 लोगों की टीम बनाकर लोगों तक पहुंचकर रोजाना बैठक लेनी है। उन्होंने

कहा कि चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे है, जिसमें दीपावली, दशहरा और नवरात्रि के पर्व भी हैं। इसके बावजूद भी प्रत्येक सैनिक को पूरी ताकत झोंकनी है। ताकि, चुनाव में हम अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दें इतनी मेहनत करनी है। घरङ्घर जाकर मतदाता सूची का मैदान करता था जो वोट अभी नए जोड़ना है उनको जुड़वाने में आम जनता की मदद करें। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के काल में रायपुर सुंदर बनाया था। जब दूर-दूर से लोग रायपुर आते थे तो इसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का हाल बेहाल है और जगह-जगह गड्ढे बनगए हैं। छत्तीसगढ़ अब गड्ढा प्रदेश बन चुका है। कांग्रेस के घोटालों के किस्से आए दिन अखबारों में छपते हैं। जिसके चलते हमारे प्रदेश की छवि अन्य प्रदेशों में खराब होती जा रही है। तीनों वार्डों की बैठक में सुनील शुक्ला, बबली सेन, आजाद साहू, दक्षिण विधानसभा संयोजक राजेंद्र, वार्ड पार्षद सरिता वर्मा, उर्मिला, राम किंकर, प्रशांत ठाकुर, सविता साहू, अनुराग अग्रवाल, सुधीर यादव, नीतू रानी गुप्ता, अरविंद यादव, शशि, अजय यादव, शांतनु, सजल, गरिमा यादव, गोपी पटेल आदि उपस्थित रहे ।

भाजपा ने की चुनाव के लिए कार्यक्रम प्रभारियों की नियुक्ति

रायपुर. छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है. हाल ही में भाजपा ने अपने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है. कुल 85 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं. 5 सीटों पर ऐलान होना बाकी है. वहीं अब भाजपा चुनाव प्रचार-प्रसार में जुट गई है. विधानसभा 2023 के चुनावी कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति की है.

बता दें कि, चुनावी कार्यक्रम के प्रभारियों की लिस्ट में 9 लोगों का नाम हैं, जिन्हें अलग-अलग नेताओं के कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है. जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम के लिए अनुराग सिंह देव, राजेश पाण्डे और विभा अवस्थी को प्रभारी बनाया गया है. वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भूपेन्द्र सवन्नी, शंकर अग्रवाल और किरण बघेल को प्रभारी नियुक्त किया गया है. गृहमंत्री शाह के कार्यक्रम के लिए संजय श्रीवास्तव, संजू नारायण सिंह ठाकुर और संध्या तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नारी शक्ति सम्मेलन : आज महिलाओं का अधिकार और रूतबा चहुओर बढ़ा है: मूणत

रायपुर। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज अग्रेसन कॉलेज में रायपुर पश्चिम विधानसभा का विधानसभा स्तरीय नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करना था मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा सांसद सरोज पाण्डेय उपस्थित थी और मुख्य आतिथ्य में राजेश मूणत की उपस्थिति रही महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा संतोष साहू के नेतृत्व में आहूत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विधानसभा की महिलाओ से उन्होंने कहा की 75 वर्ष की आजादी के पश्चात आज यह प्रथम अवसर है जब केंद्र की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए असल मायने में अनुकूल कदम उठाए इसके पूर्व में भी बहुत सी सरकारें आईं और गई बड़े बड़े विज्ञापन चलते की लड़की लड़का एक समान परंतु किसी ने भी नारियों के सशक्तिकरण के लिए संविधान सम्मत अधिकार देने का कार्य नहीं किया परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने जब से भारत की कमान संभाली शनै: शनै: नारियों के हित में कदम उठाए प्रत्येक सरकारी सुविधाओं

हेतु परिवार के मुखिया का अधिकार महिलाओ के हक में रखा आज महिलाओ का अधिकार और रूतबा चहुओर बढ़ा है और अब संवैधानिक अधिकार महिलाओ को दिए गए आज मोदी जी ने महिला आरक्षण के माध्यम से नारी शक्ति वंदन किया और आज हम सभी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हैं की हमे आपने संवैधानिक रूप से सहभागिता करने का अधिकार दिया है जिसके लिए हम आपका आभारी है उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला बोला उन्होंने कहा की एक ओर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओ को संवैधानिक अधिकार देती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जिन्होंने गंगाजल की झूठी कसमें खाकर उनके साथ छल किया जिसका जवाब छत्तीसगढ़ की महिलाएं विधानसभा चुनाव में देंगी शराबबंदी का वादा करके सत्ता पाने वाली कांग्रेस सरकार ने तो शराब की ऑनलाइन डिलिवरी चालू कर दी और सही मायने में कहा जाए तो शराब की ऑनलाइन डिलिवरी के साथ ही घरेलू हिंसा की भी ऑनलाइन डिलिवरी कांग्रेस सरकार ने की है । रायपुर पश्चिम के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने अग्रसेन कॉलेज सभाघर में आयोजित महिला सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया श्री मूणत अपने उद्बोधन की शुरुवात से ही तल्ख नजर आए उन्होंने कहा की आज छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा सबसे गंभीर मुद्दा है जिसमे भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पूर्णत: विफल है एसपी कार्यालय के सामने अनाचार जैसा जघन्य अपराध घटित हो जाता हैऔर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के मुंह से चूं तक नही निकलती यह उदासीन रवैया ही महिलाओ की असुरक्षा का प्रमुख कारण है महिला सम्मेलन में नारी शक्ति को नमन करते हुए करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के सहयोग के सुखी परिवार की कल्पना अधूरी है।

भूपेश स्पष्ट करें कि पाटन से लड़ेंगे या जगदलपुर जा रहे हैं: साव

- **कांग्रेस के नाटक का पर्दा उठने के पहले ही गिर गया है**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि वे पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे या जगदलपुर जा रहे हैं अथवा अपने लिए कोई और ऐसा ठिकाना खोज रहे हैं, जहां से विधानसभा पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को पाटन से चुनाव हारने का आत्मबोध हो गया है इसलिए पहले उनके लिए सुरक्षित सीट की पतासाजी की जा रही है। इस चक्कर में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची अधर में अटकी हुई है। भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस अन्य सीटों पर प्रत्याशी

घोषित नहीं कर पा रही है। भाजपा के उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि मुकाबले में कांग्रेस उतरे लेकिन कांग्रेस में तो उम्मीदवार चयन की बैठक में ही कांग्रेस सरकार के हुनरमंद खिलाड़ी बच्चों के खेल खेल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे इस खेल में ठीकठाक लेबल नहीं, बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि कांग्रेस 5 साल राज करने के बाद इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गई कि बैठकों पर बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री तक की टिकट घोषित नहीं कर पा रही है। इससे जाहिर है कि कांग्रेस अब न तो जनता का सामना करने की स्थिति में है और न ही भाजपा का मुकाबला करने की हैसियत में है। उन्होंने कहा कि चुनावी रणभूमि में भाजपा के योद्धा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आएं ताकि चुनाव का माहौल बने। यहां तो हालत यह है कि कांग्रेस का मनोबल पहली बार इतनी बुरी तरह गिरा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस आखिर कब मैदान में उतरेगी। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं, सब के सब उम्मीदवार सूची जारी होने को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष तारीख पर तारीख बता रहे हैं तो इनकी प्रभारी और मुख्यमंत्री कुछ और फरमा रहे हैं।

टिकट नहीं मिलने पर छलका पूर्व मंत्री का दर्द, फूट फूटकर रोने लगे

जशपुर। जिले में जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की टिकट से वंचित रखने पर उनका एक रोने वाला विडियो सामने आया है। गणेश राम भगत इस वायरल विडियो में जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक में विधानसभा की टिकट नहीं मिलने पर उपस्थित लोगों को सांत्वना दे रहे थे लेकिन, भाजपा नेताओं का आश्वासन के बाद भी टिकट नहीं दिऐ जाने की बात करते हुऐ वे अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। जशपुर जिले में इस वायरल विडियो के बाद लोग भाजपा नेताओं पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष रामप्रकाश पांडेय ने इस वायरल विडियो की पुष्टि की है, उन्होंने बताया कि जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान गणेश राम भगत काफी भावुक हो गए थे, उसी का विडियो किसी ने सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया है।

जनसूचना अधिकारियों पर राज्य सूचना आयुक्त की कार्यवाही

सूचना देने में लापरवाही पर 85 लाख रुपये का जुर्माना लगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर पिछले ढाई साल में 3 हजार 836 प्रकरणों में कुल 85 लाख 37 हजार रुपये से अधिक का अर्थदण्ड सम्बंधित जनसूचना अधिकारियों पर लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट ने मार्च 2021 से लेकर इस साल के सितम्बर माह के दौरान पारित आदेश में यह जुर्माना लगाया है।

इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, खनिज

अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरुद्ध आयोग के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है। इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस सरकार 2660 रु में धान खरीदी की: बैज

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने धान खरीदी पर केंद्र पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क़ी संसदीय क्षेत्र बनारस के किसानों को छत्तीसगढ़ के किसानों की तरह धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है बल्कि बनारस के किसान अपनी धान को औने पौने दाम 1300 रु प्रति क्विंटल की दर पर बेचने मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के बड़े नेता प्रदेश में हो रही धान खरीदी का झूठा श्रेय लेने के लिए संगठित होकर झूठ बोलते है इसका पर्दाफ़ास बनारस के किसानो के मायूस चेहरा से होता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के उपज की खरीदी नही कर रही है भाजपा के दोनों इंजन की सरकार किसानों के खिलाफ चल रही है किसानों को सिर्फ लूट रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश गुजरात और हरियाणा सहित भाजपा शासित राज्यों में किसान खेती किसानी से दूर हो रहे है उपज की सही कीमत नही मिलने के चलते हताश परेशान है कर्ज में दबे हुये है। भाजपा शासित राज्यों में महंगी बिजली समय पर रासायनिक खाद नहीं मिलना और फसल की खरीदी नहीं होना किसानों के दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है।

भूपेश सरकार देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाली सरकार: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ में रोजगार के विषय पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये वही छत्तीसगढ़ है जो रमन राज में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य हुआ करता था। रमन सरकार के दौरान सितंबर 2018 में 22.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर थी। भूपेश सरकार आने के बाद युवाओं को नौकरी और रोजगार की बेहतर अवसर मिले इसी का परिणाम

है कि विगत 1 वर्ष से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर आधा प्रतिशत से कम है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी स्थानीय युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचते रहे। भूपेश सरकार में एक लाख से अधिक पदों पर सरकारी विभागों में नियमित भर्ती हुई है, 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा हो रही है।

भाजपा के केंद्रीय नेता बताएं कि 2014 में मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, 9 साल हो गए कितने रोजगार दिए? केंद्रीय विभागों, निगम, मंडलों, नवरत्न कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 18 लाख पद रिक्त है उन पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? यूपीएससी को बाईपास करके केंद्रीय सचिवालय में संयुक्त सचिव के पदों पर मोदी के मित्र, कार्पोरेट घरानों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती करके देश के युवाओं के साथ अन्याय क्यों किया।

भीमा मंडावी की बेटी ने भाजपा के दोगला चरित्र उजागर किया

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता स्वर्गीय भीमा मंडावी की पुत्री ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी करके भाजपा के दगाबाजी चरित्र को उजागर किया है। स्व. भीमा मंडावी की पुत्री ने अपनी विधवा मां के साथ भाजपा द्वारा की गई दगाबाजी पर आक्रोश व्यक्त की है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि उनके पिता के बलिदान में क्या कमी थी? जो उनके माता को

टिकट से वंचित रखा गया है? भाजपा में समर्पित लोगों की कोई कद्र नहीं।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है भाजपा में सुहाग खोने वाली महिला की कद्र नहीं की गई है। 15 साल के भ्रष्ट, कमीशनखोर के गंभीर आरोप से घिरे रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडेय, सहित कई कर्मकांडी लोगो को प्रत्याशी बनाया गया लेकिन भीमा मंडावी की पत्नी को टिकट से वंचित कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशियों की सूची आने के बाद भगदड़ मची हुई है। भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता भाजपा के घोषित प्रत्याशियों का विरोध कर रहे है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पुतला जलाया जा रहा है, कालिख़ पोती जा रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, प्रत्याशियों के कुर्ता फाड़ा जा रहा है।

भूपेश सरकार में रचे समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान: वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि में छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर शत प्रतिशत खरा उतरी है। रमन राज के कुशासन, वादाखिलाफ़ी और भ्रष्टाचार को भी छत्तीसगढ की जनता ने भोगा है। भूपेश सरकार में अन्नदाता किसान समृद्ध हुए हैं। अधिक धान, अधिक किसान, अधिक रकबा और वादे से अधिक दाम मिला है। भूपेश

सरकार में कर्जमाफी के साथ ही किसानों का सिंचाई कर भी हुआ माफ हुआ है। किसानों को 12 हजार करोड़ से ज्यादा की बिजली रियायत कृषि पंपों पर दी गयी है। धान खरीदी 2018 में 56 लाख मिट्रिक टन थी जो 2023 में 107 लाख 53 हजार मिट्रिक टन हो गई। समर्थन मूल्य में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 2018 में 12 लाख 6000 थी जो 2023 में 24 लाख 98 हजार हो गया अर्थात समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या 2018 की तुलना में दुगने से ज्यादा हो गई है। धान की खेती का रकबा भूपेश सरकार में 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, सिंचाई का रकबा 2018 की तुलना में दुगुना हो गया है। 2018 तक केवल 4 लाख 92 हजार सिंचाई पंपों को रियायती दर पर बिजली मिलती थी 2023 में 6 लाख 86 हज़ार से अधिक किसानों के सिंचाई पंपों को नि:शुल्क और रियायती दर पर बिजली दी जा रही है।रमन सिंह चाउर वाले बाबा का मुखौटा लगाकर 36 हजार करोड़ का नान घोटाला किया, छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों का राशन खा गए।

भाजपा नेता गोयल ने की आदिवासियों समाज अनादर: मणी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मणी वैष्णव ने भाजपा विधायक प्रत्याशी विनायक गोयल द्वारा आदिवासी समाज को चोर कहने, गाली और धमकी देने की निंदा करते हुऐ कहा कि भाजपा की नजरों में आदिवासियों की क्या हैसियत है इस बात का पता चित्रकोट से भाजपा के घोषित प्रत्याशी विनायक गोयल ने बता दिया है। वायरल ऑडियो में भाजपा प्रत्याशी आदिवासी महरा समाज के एक व्यक्ति को बेहद भद्दी भद्दी गलियां दे रहे हैं और साथ ही चोर महरा जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो की बेहद शर्मनाक है। ऑडियो में भाजपा नेता विनायक गोयल आदिवासी समाज के व्यक्ति को हाथ पैर काटने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मणी वैष्णव ने कहा कि आदिवासियों के प्रति भाजपा का यह दृष्टिकोण नया नहीं है। भाजपा ने हमेशा से आदिवासी समाज को हेय दृष्टि से देखा है, उनके साथ हमेशा अन्याय और उनका दमन किया है। 15 साल जब रमन सरकार थी तो मड़कम हिडमें जैसे अनगिनत निर्दोष आदिवासी भाईयों बहनों का फर्जी एनकाउंटर नक्सली बताकर कर दिया गया। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया और उनकी हत्या कर दी गई। कई आदिवासी माताओं बहनों का बलात्कार रमन राज में हुआ। बलरामपुर में आदिवासी युवती मीना खल्को के साथ पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया और उसे गोली मारने के बाद नक्सली बता दिया।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मणी वैष्णव ने कहा रमन राज में बस्तर क्षेत्र की हजारों आदिवासी माताएं बहने गायब हो गयीं।

असामाजिक माहौल के खिलाफ जुटे खौली के युवा, खोलेंगे मोर्चा

रायपुर। ग्रामीण व्यवस्था चरमराने की वजह से मुट्ठी भर विध्नसतोषी तत्वों द्वारा ग्रामीणों को चुनौती देते हुये सरेआम असामाजिक गतिविधियां चला माहौल खराब करने से आक्रोशित खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम खौली के युवाओं ने ग्रामीणों को एकजुट करने का प्रयास शुरु कर दिया है। घर - घर घूम ग्रामवासियों से आपसी मतभेद भूल ग्रामहित में एकजुट होने के उनके मनुहार को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है जिसके चलते वे आसन्न 13 अक्टूबर को ग्रामवासियों की एक बैठक आहूत कर सामूहिक आशीर्वाद लेने की तैय्यारी

में जुटे हैं। इधर खौली में व्याप्त अघोषित भट्ठी के माहौल की वजह से आसपास के ग्रामों का माहौल दूषित होने की शिकायत पर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने थाना प्रभारी के के के कुशवाहा से प्रत्यक्ष मुलाकात न हो पाने की वजह से व्हाट्स ऐप के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर ठोस प्रभावी कार्यवाही का आग्रह किया है

ज्ञातव्य हो कि कुछ समय पूर्व तक अपने कसे हुये ग्रामीण व्यवस्था के लिये मशहूर ग्राम खौली की व्यवस्था आपसी खींचतान की वजह से चरमरा गया है जिसकी फायदा ग्राम के विध्नसतोषी तत्व असमाजिक गतिविधियों में लिप्त हो उठा रहे हैं । ग्रामीण सूत्रों के अनुसार मुट्ठी भर इन तत्वों ने न केवल ग्राम में अघोषित भट्ठी का? माहौल बना रखा है वरन् एक ने तो शराब के साथ साथ गांजा बेचना भी शुरू कर दिया है। नहर पार व उसके नीचे, अंबेडकर चौक, तालाब के पास, खौली से चंदखुरी फार्म मुख्य सड़क मार्ग पर खौली के पेट्रोल पंप के पास इनका अड्डा रहता है, इसके सिवा ये तत्व मोबाइल संपर्क से भी पियक्कड़ों को शराब उपलब्ध कराते हैं। अवैध शराब बिक्री पर काफी हद तक अंकुश लगा चुके आसपास के ग्रामों के पियक्कड़ों का भी मजमा यहां लगता है । इसकी वजह से ग्राम का माहौल काफी दूषित रहता है और सभ्य नागरिकों , महिलाओं व नौनिहालों का राह चलना भी दूभर हो चला है।

चुनाव आयोग ने दो कलेक्टर व तीन एसपी को हटाया

- **बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को हटाया गया**
- **दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण और राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा भी हटाए गए**
- **सूची में बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव का नाम भी शामिल**

रायपुर। आचार संहिता लगने के तीन दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने और

पारदर्शिता को प्रभावित करने की शिकायतों पर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कुल आठ अधिकारियों को हटा दिया है। इनमें दो कलेक्टर, तीन एसपी, दो एडिशनल एसपी और एक अन्य अधिकारी है।

जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें बिलासपुर कलेक्टर संजय झा (बैच 2011), रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा (बैच 2012), राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा (बैच 2010), दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा(2014) और कोरबा एसपी उदय किरण (बैच 2015) शामिल है। इसी तरह एडिशनल एसपी में बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी व दुर्ग एडिशनल एसपी संजय ध्रुव के नाम शामिल हैं।

नान के विशेष सचिव व मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी का नाम भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं। हटाए गए अधिकारियों के स्थान पर तत्काल इनके कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार सौंपने को कहा गया है। साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन पदों के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से तीन-तीन नामों का पैनल मंगाया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.